सूर्योदय - 06:26
सूर्यास्त - 05 : 44

अधिकतम तापमान 32.0°
न्यूनतम तापमान 19.0°

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

ओपन सर्च

RNI No.DELHIN/2015/66886

खबरें और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

Mob. : 9210092542
opensearchnews@gmail.com

E-mail | opensearchdelhi@gmail.com
Facebook | https://www.facebook.com/opensearch.co.in
Website | www.opensearch.co.in

वर्ष : 12 अंक : 331 नई दिल्ली, गुरूवार 05 नवम्बर-2026
नई दिल्ली, हरियाणा, बिहार से प्रकाशित
` मूल्य : 02 रूपए | पृष्ठ : 08

केंद्र ने 'विस्तार' योजना को दी मंजूरी, 4,371.10 करोड़ रुपए होंगे खर्च

नई दिल्ली.एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 'विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिकल ट्रांसफॉरमेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च (विस्तार)' स्कीम को मंजूरी दी। विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप, विस्तार योजना को समयबद्धता, डेटा की सटीकता, सामंजस्यपूर्ण और एआई-तैयार डेटासेट के साथ अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने के लिए एक गतिशील, वास्तविक समय और भविष्य के लिए तैयार आधिकारिक सांख्यिकीय ढांचे को स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

कैबिनेट के मुताबिक, यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी और इसका कुल बजट 4,371.10 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। विस्तार योजना तत्काल नीतिगत जरूरतों के आधार पर संसाधनों को गतिशील रूप से आवंटित करने की रणनीतिक लचीलापन प्रदान करेगी। यह बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने, पद्धतिगत अनुसंधान, डिजिटल परिवर्तन और राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी। विस्तार योजना में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सभी सांख्यिकीय और डेटा प्रबंधन गतिविधियां शामिल होंगी, और यह देश की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विस्तार योजना के तीन प्रमुख घटक हैं, जिसमें व्यापक सांख्यिकीय कार्य और इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाना, सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन (एसएसएस) और आर्थिक जनगणना (ईसी) शामिल हैं। व्यापक सांख्यिकीय संचालन और इकोसिस्टम सुदृढ़ीकरण' घटक के तहत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 16वें एफसी चक्र के दौरान 59 सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले 43 प्रमुख सर्वेक्षण कराए गए थे।



कैबिनेट के मुताबिक, यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी और इसका कुल बजट 4,371.10 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। विस्तार योजना तत्काल नीतिगत जरूरतों के आधार पर संसाधनों को गतिशील रूप से आवंटित करने की रणनीतिक लचीलापन प्रदान करेगी

इन नए सर्वेक्षणों से विभिन्न क्षेत्रों में डेटा की महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर होगी और समय पर लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप संभव हो सकेंगे। सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन (एसएसएस) घटक के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांख्यिकीय क्षमताओं को बदलने के लिए, उन्हें एक नए डिजाइन किए गए और परिणाम-आधारित ढांचे (एसएसएस 2.0) के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। आर्थिक जनगणना (ईसी) घटक के अंतर्गत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से 8वीं आर्थिक जनगणना (ईसी) आयोजित करेगा।

महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना से भारत की अन्य देश पर कम होगी निर्भरता : मोदी

नई दिल्ली। कैबिनेट की ओर से 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' को मंजूरी देने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे भारत की अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि लिथियम, निकेल, कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिज ईवी, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी हैं।

फिर भी, हम रिफाइन की गई सामग्रियों के आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं। मौजूदा स्थिति को समाप्त करने के लिए कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दी है। पोस्ट में आगे कहा कि इस योजना की खासियत नए महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र, निवेश को बढ़ावा



देने के लिए पूंजीगत सहायता, घरेलू स्तर पर अधिक मूल्य संवर्धन और मजबूत सप्लाई चेन है। अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा सिद्धांत स्पष्ट है... भारत के पास भविष्य की तकनीकें विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए! कैबिनेट ने पांच वर्षों की अवधि के लिए 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 2,814 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।

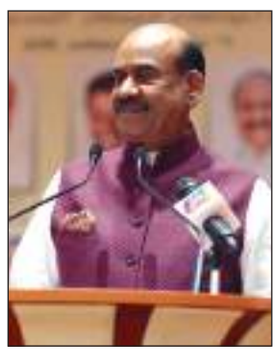
बिरला ने संसद की तर्ज पर राज्य विधानमंडलों के लिए डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने का आह्वान किया

अधिक प्रभावी विधायी निगरानी के लिए केंद्र और राज्य मिलकर लेखापरीक्षा एवं मूल्यांकन की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित करें : लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला

तिरुवनंतपुरम.एजेंसी

संसद तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों के सभापतियों के दो दिवसीय सम्मेलन के तिरुवनंतपुरम में सम्पन्न होने पर समापन संबोधन देते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी समितियों के कामकाज में प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक समावेश का आह्वान किया। संसद की समितियों के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म की तर्ज पर राज्य विधानमंडलों के लिए एक डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने कहा कि इससे लेखापरीक्षा टिप्पणियों की व्यवस्थित निगरानी, अनुवर्ती कार्रवाई की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समयबद्ध जांच और निस्तारण सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

इस बात पर बल देते हुए कि प्रौद्योगिकी संस्थागत परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बननी चाहिए, बिरला ने कहा कि डिजिटल नवाचारों को अपनाने से विधायी निगरानी की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही, प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि



तकनीकी प्रगति सदैव मानवीय मूल्यों, विवेक और संवेदनशीलता पर आधारित रहनी चाहिए। प्रौद्योगिकी को संस्थागत जवाबदेही सुदृढ़ करने और निर्णय लेने की गुणवत्ता बेहतर बनाने में सहायक होना चाहिए, लेकिन यह कभी भी मानवीय विवेक और निर्णय क्षमता का विकल्प नहीं हो सकती।

उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सृजित और प्राप्त किए जाने वाले आंकड़ों की सटीकता, प्रामाणिकता और निष्पक्षता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित शासन की विश्वसनीयता अंततः उन सूचनाओं की प्रमाणिकता पर निर्भर करती है, जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

पीएम मोदी ने शरद पवार को फोन कर जाना हाल, स्वास्थ्य पर चर्चा से महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ी हलचल



पुणे/नई दिल्ली.एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एनसीपी(एसपी) अध्यक्ष शरद पवार को फोन किया और उनका हालचाल पूछा। इस बात की पुष्टि शरद पवार के पारिवारिक मित्र और करीबी सहयोगी विट्ठल मनियार ने की है। हालांकि, प्रधानमंत्री के इस फोन कॉल ने महाराष्ट्र में राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। अस्पताल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मनियार ने बताया कि पीएम मोदी ने वरिष्ठ नेता से आग्रह किया कि वे अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और आराम करें। पीएम मोदी ने शरद पवार से कहा, सुप्रिया और हम देश संभाल लेंगे। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और आराम करें। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। पीएम मोदी के फोन कॉल के बाद पवार के अस्पताल में भर्ती होने की खबर ने राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया। पीएम मोदी ने सुबह-सुबह फोन करके शरद पवार का हाल-चाल पूछा था। पवार ने फोन करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे आराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप सभी के रहते मुझे देश की कोई चिंता नहीं है।

दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत ने महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों को लेकर मीडिया में फिर से अटकलें तेज कर दी हैं। हालांकि उनके करीबी सहयोगियों का कहना है कि यह केवल पवार की सेहत के बारे में पूछा गया एक शिष्टाचार भरा कॉल था। मनियार ने पुष्टि की कि वरिष्ठ नेता की हालत स्थिर है और कोई गंभीर समस्या नहीं है। उनकी सेहत काफी अच्छी है; कोई गंभीर बात नहीं है।

इंसाफ रैली में राहुल गांधी बोले-'पंजाब में ऐसी सरकार चाहिए, जो जनता के लिए काम करे'

पंजाब.एजेंसी

लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में 'इंसाफ रैली' में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और पंजाब की 'आप' सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब को ऐसी सरकार चाहिए जो यहां की जनता के लिए काम करे। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब की सरकार दिल्ली से नहीं चलाई जा सकती। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है तो यहां सरकार पंजाब से ही चलाई जाती है। हमारा मुख्यमंत्री पंजाब का मुख्यमंत्री होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में पंजाब को न हिंदुस्तान का गृह मंत्री चलाता है और न ही दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री चलाता है। आज दिल्ली से पंजाब की सरकार चलाई जा रही है। आधी लगाम अमित शाह ने और आधी केजरीवाल ने पकड़ रखी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तीखा हमला



राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब की सरकार दिल्ली से नहीं चलाई जा सकती। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है तो यहां सरकार पंजाब से ही चलाई जाती है। हमारा मुख्यमंत्री पंजाब का मुख्यमंत्री होता है

किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के धमकाने पर मोदी ने 5 मिनट के अंदर यूएस डील साइन कर दी।

इस बारे में कैबिनेट तक को जानकारी नहीं दी गई और न ही किसी ब्यूरोक्रेट को बताया गया। मोदी ने हिंदुस्तान के किसानों और एमएसएमई का डेटा ट्रंप के हवाले कर दिया। राहुल ने कहा कि अमित शाह लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं लेकिन पूरा देश जानता है, उन्होंने जेल में गैंगस्टर्स पाल रखे हैं। अमित शाह बताएं कि मणिपुर में क्या स्थिति है क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था के चलते नरेंद्र मोदी मणिपुर भी नहीं जा सकते। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को नशे में झोंकने वाली 'आप' सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। प्रदेश की जनता इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगी। उन्होंने कहा कि भगवंत मान जब सांसद थे तो हमारे पास बैठकर चुटकुले सुनाते थे। भगवंत मान का शराब पीना उनका व्यक्तिगत मामला है लेकिन अगर पंजाब नशे से लड़ना चाहता है, तो यहां का मुख्यमंत्री हर शाम नशा नहीं कर सकता। राहुल ने कहा कि पंजाब में नशा सबसे बड़ा मुद्दा है।

भारत के लिए महासागर दूर या अनजाने नहीं है, स्वतंत्र व नियम आधारित व्यवस्था के पक्षधर : राजनाथ

नई दिल्ली.एजेंसी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र का भविष्य केवल तकनीक से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात से तय होगा कि विभिन्न देश उस तकनीक का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करते हैं। किस तरह की साझेदारी बनाते हैं और एक-दूसरे के बीच कितना विश्वास कायम करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस सामूहिक प्रयास में योगदान देने के लिए तैयार है।

'इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग -2026' (आईपीआरडी-2026) के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के लिए महासागर कभी दूर या अनजाने क्षेत्र नहीं रहे हैं। सदियों से भारतीय नाविक इन समुद्री रास्तों से होकर गुजरते रहे हैं। वे अपने साथ केवल सामान ही नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और मानवीय संबंधों को भी लेकर



चलते थे। यही प्रमुख कारण है कि भारत ने हमेशा स्वतंत्र, खुले और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जिम्मेदारी के साथ योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री जिम्मेदारियां उसकी राष्ट्रीय तटरेखा तक सीमित नहीं हैं। भारत लगातार एक खुली, समावेशी और नियमों पर आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन करता रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज वैश्विक समुद्री सुरक्षा का माहौल जानबूझकर किए जा रहे व्यापारिक व्यवधानों के कारण दबाव में है। समुद्री मार्गों पर आवाजाही की स्वतंत्रता को खुली चुनौती दी जा रही है और संकरे समुद्री रास्तों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

विद्या भारती द्वारा आयोजित 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह-का समापन समारोह

ओपन सर्च/ओ पी उनियाल

देहरादून। शिक्षा के सीथ शारिरीक विकास के महत्व पर बल देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्', अर्थात स्वस्थ शरीर ही जीवन के कर्तव्यों और लक्ष्यों की पूर्ति का आधार है। आज गाजियाबाद में विद्या भारती द्वारा आयोजित 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह-2026 के समापन समारोह के अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया तथा सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों की सहभागिता इस आयोजन को विशेष बनाती है। हिमालय के सीमांत क्षेत्रों से लेकर कन्याकुमारी और पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर पूर्वोत्तर तक के खिलाड़ियों का एक मंच पर एकत्र होना लघु भारत का दर्शन कराता है।

दीवाली से पहले बजी महिलाओं के मोबाइल में खुशी की घंटी

महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त जारी, महिलाओं में उत्साह का माहौल



ओपन सर्च. संवाददाता

रायपुर। दीवाली से पहले बजी महिलाओं के मोबाइल में खुशी की घंटीछत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने की दिशा में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की माताओं-बहनों को दीवाली के पहले एक बड़ी सौगात मिली है। राज्योत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त जारी की।

प्रदेश की 67 लाख 40 हजार 410 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कुल 632 करोड़ 63 लाख 67 हजार 750 रुपये की राशि अंतरित की गई

इसके अंतर्गत प्रदेश की 67 लाख 40 हजार 410 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कुल 632 करोड़ 63 लाख 67 हजार 750 रुपये की राशि अंतरित की गई। दीवाली से पहले महतारी वंदन योजना की 33 वीं किस्त जारी होने से महिलाओं और उनके परिवार में उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ शासन की इस निरंतर वित्तीय सहायता से प्रदेश की महिलाएं अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ परिवार की आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय योगदान दे रही हैं। ई-केवाईसी पूर्ण करा चुकीं 67 लाख 33 हजार 502 महिला हितग्राहियों को लाभ मिला। इसके साथ ही नियद नेल्ला नार कैंप क्षेत्रों की 6,908 महिलाओं को भी योजना की 33वीं किस्त प्रदान की गई। महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

नीतीश कुमार से मिले सीएम सम्राट चौधरी, गंगा से गाद निकालने के समझौते की दी जानकारी

गंगा से गाद निकालने को लेकर नीतीश कुमार ने जो अभियान चलाया था, वह सफल हुआ : सम्राट चौधरी

ओपन सर्च. संवाददाता

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा से गाद निकालने को लेकर नीतीश कुमार ने जो अभियान चलाया था, वह सफल हुआ है।

इस संबंध में दिल्ली में एक बड़ा समझौता हुआ है, जिससे बिहार को बाढ़ से राहत दिलाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को गंगा से गाद निकालने के लिए भारत सरकार के साथ हुए समझौते की जानकारी दी।

नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को बार-बार उठाया था। उनके काम और सपनों को पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। सम्राट



मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को गंगा से गाद निकालने के लिए भारत सरकार के साथ हुए समझौते की जानकारी दी। नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को बार-बार उठाया था। उनके काम और सपनों को पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है

चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारत सरकार के साथ समझौता हुआ है। इसके तहत गंगा सहित अन्य प्रमुख नदियों से करीब चार लाख क्यूबिक मीटर गाद निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निकाली गई गाद का इस्तेमाल बिहार में भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे दो बड़े फायदे होंगे। बिहार में बाढ़ की स्थिति में राहत मिलेगी और खेतों की मिट्टी के कटाव से बचाव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार और सड़क परिवहन मंत्रालय को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में बेहतर व्यवस्था और सुशासन स्थापित किया है तथा राज्य को संगठित अपराध से मुक्त किया है।

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मुलाकात के दौरान रेलवे मंत्री से छठ और दीपावली पर बिहार आने वाले लोगों के लिए बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। पिछली बार 10 हजार से अधिक जोड़ी ट्रेनें चलाई गई थीं। इस बार उससे अधिक ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया गया है।

मणिपुर में प्रतिद्वंद्वी नागा गुटों के बीच हुई गोलीबारी में चार उग्रवादी मारे गए

इंफाल.एजेंसी

मणिपुर के नोनी जिले में बुधवार को प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच हुई गोलीबारी में कम से कम चार उग्रवादी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, नागा बहुल जिले के खौपुम क्षेत्र के ताओडाईजांग गांव में सुबह-सुबह प्रतिद्वंद्वी नागा उग्रवादी संगठनों (जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट-जेनचुई और जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट-कामसन शामिल) से जुड़े संदिग्ध कार्यकर्ताओं के बीच भारी गोलीबारी शुरू हो गई। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, गोलीबारी कई घंटों तक चली, जिसमें दोनों संगठनों का एक-एक कार्यकर्ता मारा गया। मारे गए उग्रवादियों के शव स्थानीय निवासियों ने बरामद किए। घटना के बाद, महिलाओं सहित स्थानीय निवासी प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच और हिंसा को रोकने के प्रयास में घटनास्थल पर पहुंचे।

जनसमस्याओं की अनदेखी पर मुख्यमंत्री एक्शन मोड में, गुरुग्राम में विभिन्न अधिकारियों पर लिया एक्शन

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत दिसंबर 2027 के अंत तक 400 से अधिक सरकारी स्कूलों को नए भवन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं मिलें।

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी बुधवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान एक स्कूल के भवन के जीर्णोद्धार से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए दी। बैठक में कुल 15 परिवाद सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 11 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि शेष 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों में की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में बेहतर, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाना सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उसका त्वरित एवं प्रभावी निवारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नगर परिषद पटौदी-जटौली मंडी क्षेत्र से संबंधित एक शिकायत की सुनवाई करते हुए गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनाने तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं की अनदेखी के मामले को गंभीरता से लिया। जांच में सामने आया कि तत्कालीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर और म्युनिसिपल इंजीनियर ने सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर प्रॉपर्टी आईडी बनाई थीं। मुख्यमंत्री ने ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने पर दोनों अधिकारियों की तीन माह तक 50 प्रतिशत सैलरी काटने, उनके चार्जशीट करने तथा हरियाणा के एनसीआर जिलों से बाहर तबादला करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यों में लापरवाही और नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजन के हितों से जुड़े मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता एवं रखरखाव से जुड़ी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए। उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के माध्यम से प्रत्येक जोन में तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने को कहा, जिसमें एक सरकारी अधिकारी भी शामिल होगा। ये कमेटियां गुरुग्राम नगर निगम के छह तथा मानेसर नगर निगम के दो जोन में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति और साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में सार्वजनिक शौचालयों के बेहतर रखरखाव और नियमित स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में एक नागरिक की शिकायत पर सुनवाई करते हुए नगर निगम गुरुग्राम के पटवारी द्वारा गलत व्यवहार किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया। शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार की बात सामने आने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की जिम्मेदारी है।

पदयात्रा की तैयारियों का महापौर ने लिया जायजा, सेक्टर-12 में किया स्थल निरीक्षण

गीता देवी/ओपन सर्च ब्यूरो



करनाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के करनाल आगमन पर आयोजित होने वाली 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा की तैयारियों को लेकर महापौर रेणु बाला गुप्ता लगातार सक्रिय हैं। आयोजन को सुव्यवस्थित और सफल बनाने के उद्देश्य से महापौर ने सेक्टर-12 स्थित पदयात्रा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मंगला, जगमोहन आनंद, जिला प्रभारी जवाहर यादव और रोहतक के महापौर राम अवतार के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और कार्यक्रम में पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। महापौर ने व्यवस्थाओं में आपसी समन्वय और समयबद्ध तैयारी पर जोर देते हुए कहा कि इतने बड़े आयोजन में प्रत्येक छोटी-बड़ी व्यवस्था का दुरुस्त होना जरूरी है, ताकि कार्यक्रम में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो। इस अवसर पर महापौर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि अमित शाह का करनाल आगमन शहर के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी एवं समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि संगठन की एकजुटता, कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनसहभागिता किसी भी बड़े आयोजन की सफलता के महत्वपूर्ण आधार हैं। महापौर ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों और बेहतर तालमेल से इस आयोजन को सुव्यवस्थित एवं यादगार बनाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पूरी सक्रियता के साथ तैयारियों में जुटें और कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करें।

शहीद स्मारक के लोकार्पण पर शाह का हरियाणा की धरती पर भव्य स्वागत करेगा प्रदेश : गंगवा

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का 5 नवंबर को अंबाला आगमन प्रदेश के लिए गौरव और उत्साह का बड़ा अवसर है। हरियाणा की वीरभूमि पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में हरियाणा ने विकास के साथ-साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली इतिहास और वीर परंपराओं को नई पहचान देने का काम किया है। अंबाला में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर बलिदानियों को समर्पित भव्य शहीद स्मारक का लोकार्पण इसी सोच का प्रतीक है। यह स्मारक प्रदेशवासियों के लिए गर्व का केंद्र बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वीरों की शौर्यगाथा से जोड़ने का काम करेगा। गंगवा ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी ने हमेशा देश की रक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को जन्म दिया है।

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी इस धरती के वीरों ने अदम्य साहस और बलिदान की मिसाल पेश की थी। अंबाला में बनकर तैयार हुआ यह स्मारक उन ज्ञात-अज्ञात बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिनके संघर्ष और त्याग की बदौलत देश की आजादी की नींव मजबूत हुई। यहां 700 से अधिक वीर बलिदानियों के नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किए गए हैं। आधुनिक तकनीक और आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा को इस तरह सहेजा गया है कि हर आगंतुक उस दौर के संघर्ष और बलिदान को महसूस कर सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा हरियाणा के लिए एक यादगार अवसर होगा। शहीद स्मारक का लोकार्पण प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा। यह केवल ईंट-पत्थर से बना स्मारक नहीं, बल्कि देश भक्ति, त्याग, साहस और राष्ट्रीय स्वाभिमान की जीवंत प्रेरणा है। अमित शाह अंबाला के गांधी ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गंगवा ने प्रदेशवासियों से इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री नायब सैनी का गर्मजोशी से स्वागत करने का आह्वान किया।

उत्तराखंड की बेशकीमती सरकारी जमीनों और ऐतिहासिक धरोहरों को निजी हाथों में सौंप रही भाजपा सरकार : कुमारी सैलजा

ओपन सर्च ब्यूरो



नई दिल्ली/सिरसा। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य एवं उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने उत्तराखंड की बेशकीमती सरकारी जमीनों और ऐतिहासिक धरोहर भवनों को निजी संस्थाओं को सौंपे जाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य की महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों के आवंटन में पारदर्शिता और निर्धारित नियमों की अनदेखी की जा रही है। कुमारी सैलजा ने नई दिल्ली में जारी बयान में दावा किया कि उत्तराखंड के 13 में से 12 जिलों की लगभग 40 सरकारी संपत्तियों और ऐतिहासिक भवनों को निजी क्षेत्र को सौंपने की प्रक्रिया अपनाई गई है। इनमें ऋषिकेश की आईडीपीएल की 633 एकड़ भूमि, डाकपत्थर की लगभग 190 एकड़ जमीन, रानीबाग की एचएमटी भूमि तथा नैनीताल, धनौल्टी और टिहरी की महत्वपूर्ण संपत्तियां शामिल हैं। सांसद ने कहा कि सरकारी अभिलेखों के अनुसार जनवरी और नवंबर 2025 में विभिन्न भूमि आवंटन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी दी गई।

सैलजा ने आरोप लगाया कि लगभग 1,080 एकड़ सरकारी भूमि से जुड़े निर्णयों में संबंधित विभागों और मंत्रियों की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। कुमारी सैलजा ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट तथा हरिद्वार और ऋषिकेश के ऐतिहासिक भवनों को निजी संस्थाओं को दिए जाने की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की।

दिवाली पर प्रदेश के अस्पताल अलर्ट मोड पर, आरती सिंह राव ने जारी की एडवाइजरी

अस्पतालों में बर्न, ईएनटी और इमरजेंसी बेड आरक्षित, डॉक्टर रहेंगे ऑन-कॉल

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दिवाली पर्व के दौरान अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए विशेष सलाह जारी की है। त्योहार के समय पटाखों और अन्य हादसों के कारण जलने और सांस संबंधी समस्याओं के मामलों में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए उन्होंने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बर्न-वार्ड अलग से तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। आपातकालीन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में ब्रोंकोडायलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और बर्न ट्रीटमेंट किट जैसी आवश्यक दवाओं व चिकित्सा आपूर्ति का पहले से ही प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा गया है। आतिशबाजी या किसी भी प्रकार दुर्घटना के शिकार लोगों का त्वरित इलाज संभव हो सके, इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में 20 से अधिक बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिवाली के दिन सामान्य दिनों की तुलना में सड़क हादसों, झुलसने और आंखों की चोटों की घटनाओं में इजाफा होता है, जिसे देखते हुए इमरजेंसी विभाग के अलावा नेत्र रोग (ऑप्थैल्मोलॉजी), आर्थोपेडिक और सर्जरी विभागों में भी बेड सुरक्षित रखे जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया है कि नेत्र रोग, आर्थोपेडिक और सर्जरी विशेषज्ञों को अलर्ट मोड और ऑन-कॉल ड्यूटी पर रखा जाए ताकि पीड़ितों को तुरंत और प्रभावी इलाज मिल सके। दिवाली के दिन किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों को तैनात रहने का आदेश जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त बर्न मरीजों के लिए पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर, बेड, आई/वी स्टैंड, आई/वी सोलूशन्स और एंटीबायोटिक्स की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। दिवाली पर्व के दौरान चिकित्सा कर्मियों और विशेषज्ञों को शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी तथा आई और ईएनटी विशेषज्ञों की टीमें अस्पतालों में मौजूद रहेंगी।

सोनीपत में 5 से 20 नवंबर तक सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम : डीसी नेहा सिंह

ओपन सर्च ब्यूरो

सोनीपत। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा एहतियाती कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इन निर्देशों के तहत सोनीपत जिले में 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक सरकारी एवं निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, जबकि शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम यानी घर से कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि सीएक्यूएम के निर्देशानुसार सभी सरकारी विभागों, निजी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य प्रतिष्ठानों को इन आदेशों की सख्ती से पालना करनी होगी। सभी विभागाध्यक्ष एवं संस्थान प्रमुख कर्मचारियों के लिए उचित रोस्टर एवं रोटेशन व्यवस्था तैयार करेंगे, ताकि कार्यालयों का आवश्यक कार्य प्रभावित न हो और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगी, जहां परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के कारण वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं है। हालांकि, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने प्रशासनिक, कॉरपोरेट, अकाउंट, मानव संसाधन एवं अन्य गैर-निर्माण संबंधी कार्यालयों या अनुभागों में जहां संभव हो, 50% भौतिक उपस्थिति और शेष कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करनी होगी। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक तथा अन्य ऐसे कार्यालयी स्टाफ के लिए भी यह व्यवस्था लागू रहेगी, जहां वर्क फ्रॉम होम संभव है।

सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी मातृ-नवजात शिशु देखभाल पहल शुरू

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं की जान बचाने की तैयारियों को और मजबूत करते हुए हरियाणा सरकार प्रदेश में लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत से 19 अतिरिक्त नवजात वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने जा रही है। प्रदेश की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू) में पहले से 54 नवजात वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। इन 19 नए वेंटिलेटर के जुड़ने से गंभीर परिस्थितियों में नवजात शिशुओं को समय पर श्वसन सहायता उपलब्ध करवाने की क्षमता और मजबूत होगी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों को एकीकृत मातृ-नवजात शिशु देखभाल इकाइयों के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेशव्यापी पहल कर रही है। इसके तहत चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त परिस्थितियों में अस्पताल में उपचार के दौरान मां को अपने नवजात शिशु के साथ रहने की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने यह जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य अस्पताल में भर्ती नवजात शिशुओं को उनकी माताओं से अनावश्यक रूप से अलग होने से बचाना है।

इसके लिए विशेष चिकित्सा उपचार के साथ मां की निरंतर उपस्थिति, स्तनपान में सहयोग और शिशु की देखभाल में परिवार की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत माताओं को अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान अपने शिशुओं के पास रहने और प्रशिक्षित डॉक्टरों तथा नर्सों की देखरेख में उनकी देखभाल में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, यह पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के 'जीरो सेपरेशन' यानी मां और नवजात को अलग न रखने के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के तहत चिकित्सकीय रूप से संभव होने पर विशेष नवजात शिशु देखभाल की आवश्यकता वाले मामलों में भी मां और शिशु को साथ रखने पर जोर दिया जाता है। यह मॉडल विशेष रूप से समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रखने, दूध पिलाने में सहायता, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने और निरंतर चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता हो सकती है।

नवजात शिशु की देखभाल में सक्रिय भागीदार बनेंगी माताएं

मातृ-नवजात शिशु देखभाल इकाई (एमएनसीयू) की प्रमुख विशेषताओं में कंगारू मदर केयर (केएमसी) शामिल है। इसमें नवजात शिशु को मां या किसी अन्य उपयुक्त देखभालकर्ता के सीने से सीधे त्वचा के संपर्क में रखा जाता है। यह प्रक्रिया शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने, स्तनपान को बढ़ावा देने तथा मां और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं के लिए लाभदायक है। इस एकीकृत देखभाल मॉडल के तहत स्वास्थ्य विशेषज्ञ माताओं को स्तनपान, नवजात शिशु के पोषण, स्वच्छता और बीमारी के चेतावनी संकेतों की पहचान करने के संबंध में भी मार्गदर्शन देंगे।

रबी सीजन में किसानों को न हो पानी की कमी, नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए बढ़ाएं निगरानी और जन भागीदारी : सिंचाई मंत्री

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चालू रबी सीजन के दौरान प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का समुचित प्रबंध किया जाए ताकि फसलों की बिजाई प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी की सीमित उपलब्धता के बावजूद राज्य सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हर क्षेत्र के किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिले। इसके लिए वितरण प्रणाली की समीक्षा के साथ-साथ नहरी पानी की निरंतर निगरानी भी की जा रही है।

वे यहां के पानी की आपूर्ति को लेकर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक मे बाढ़ नियंतत्रण उपायों के साथ-साथ वन विभाग से संबंधित स्वीकृतियों, भूमि की निशानदेही तथा पंपों की उपलब्धता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल भी बैठक में मौजूद रहे। श्रुति चौधरी ने निर्देश दिए कि पानी के आवंटन से संबंधित पुराने रिकॉर्ड, निर्धारित मानदंडों का आकलन किया जाए और समय-समय पर पानी की उपलब्धता, सिंचित क्षेत्र और किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार इसकी समीक्षा भी की जाए। उन्होंने कहा की नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए लोगों को जागरुक किया जाए और इस मुहिम में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। सिंचाई मंत्री ने कहा कि वन संबंधी स्वीकृतियों के चलते विकास कार्य अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने चाहिए। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए। इसी प्रकार, सिंचाई परियोजनाओं एवं पंपिंग व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में भी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान का शुभारंभ, 1400 छात्राओं ने लिया भाग



ओपन सर्च ब्यूरो

सोनीपत। बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान का शुभारंभ बुधवार को सोनीपत के मुरथल अड्डा स्थित पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जेआरसी व एमडीडी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। 100 दिवसीय इस जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ जिला समन्वयक डॉ. राज सिंह सांगवान ने किया। कार्यक्रम में करीब 1400 छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान डॉ. राज सिंह सांगवान ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बाल विवाह, ऑनलाइन शोषण, साइबर अपराध, ऑनलाइन ग्रूमिंग तथा बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाली एक सामान्य सी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी कई बार बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण, जबरन संबंधों अथवा कम उम्र में विवाह के दबाव जैसी गंभीर परिस्थितियों तक पहुंचा सकती है। इसलिए बच्चों को यह समझना जरूरी है कि ऑनलाइन शुरू होने वाला शोषण भी शारीरिक शोषण जितना ही गंभीर है। शोषण चाहे ऑनलाइन हो या प्रत्यक्ष रूप से, बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल राजेश कुमारी ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा होने के साथ-साथ बच्चों के भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्या है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने छात्राओं को बताया कि किसी भी ऑनलाइन शोषण की स्थिति में डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने चाहिए तथा साइबर अपराध पोर्टल www. cybercrime. gov.in, आपातकालीन सहायता नंबर 112 या बाल सहायता नंबर 1098 पर संपर्क कर मदद प्राप्त की जा सकती है।

युवा समाज को संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने में निभाएं सक्रिय भूमिका : विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। हरियाणा विधान सभा की ओर से बुधवार को हरियाणा युवा संवाद-2026 का आयोजन किया गया। इसमें 15 राज्यों के 90 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। सामाजिक संस्था राजधानी युवा संसद के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति, संवैधानिक मूल्यों और महिला सशक्तीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

संवाद की प्रतियोगिता में जानवी शर्मा ने प्रथम, आरजू पाराशर ने द्वितीय तथा अक्षय कुमार झा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से आह्वान किया कि वे समाज को संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इससे पूर्व, कार्यक्रम का शुभारंभ विधान सभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम के बाद विस अध्यक्ष ने युवाओं प्रतिभागियों के साथ चाय पर मंत्रणा भी की। विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि भारतीय संस्कृति का मूल भाव स्वयं से पहले दूसरों के हितों और कल्याण की चिंता करना है। यही भावना समाज में परस्पर सहयोग, सद्भाव और समरसता को मजबूत बनाती है।

हरविन्द्र कल्याण ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से आह्वान किया कि वे समाज को संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभाएं

उन्होंने कहा कि संविधान हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके मूल्यों को समझना और उन्हें अपने आचरण में उतारना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए।

उनकी जयंती केवल आयोजन करने तक सीमित न रहे, बल्कि उनके विचारों और जीवन मूल्यों को अपने व्यवहार में भी अपनाना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने दायित्वों के प्रति सावधान रहना चाहिए। दुनिया के मौजूदा हालात का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसका बड़ा कारण जीवन मूल्यों में सौहार्द और सहिष्णुता की कमी तथा भौतिक विकास की अंधाधुंध दौड़ है।

इसके विपरीत, भारतीय संस्कृति हमें सहिष्णुता, परस्पर सम्मान और सबके कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कल्याण ने कहा कि युवाओं को आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी क्षमताओं और दक्षताओं का विकास करना चाहिए, लेकिन विकास तभी सार्थक होगा, जब इसके साथ जीवन मूल्यों और संस्कारों को भी बनाए रखा जाए।

'दिमागी नक्सल' वाला फ्लॉप बयान दोहरा रहे पीएम मोदी, वोट चोरी पर उनके पास कोई जवाब नहीं : खड़गे

नई दिल्ली (एजेंसी)



खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी अपने फ्लॉप हो चुके 'दिमागी नक्सल' वाले बयान को बार-बार दोहरा रहे हैं। उनके पास वोट चोरी और राहुल गांधी की उस खुली चुनौती का कोई जवाब नहीं है, जिसमें पूछा गया है कि उन्होंने भारतीय हितों को विदेशी ताकतों के सामने कैसे गिरवी रखा।' अमित शाह के उस बयान पर भी खड़गे ने सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने तीन करोड़ मतदाताओं को घुसपैठिया बताया था

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी और विदेशी ताकतों के सामने भारतीय हितों को गिरवी रखने से जुड़े सवालों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।

खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी अपने फ्लॉप हो चुके 'दिमागी नक्सल' वाले बयान को बार-बार दोहरा रहे हैं। उनके पास वोट चोरी और राहुल गांधी की उस खुली चुनौती का कोई जवाब नहीं है, जिसमें पूछा गया है कि उन्होंने भारतीय हितों को विदेशी ताकतों के सामने कैसे गिरवी रखा।'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर भी खड़गे ने सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने तीन करोड़ मतदाताओं को घुसपैठिया बताया था। खड़गे ने पूछा कि इतने वर्षों तक गृह मंत्री रहने के दौरान शाह क्या कर रहे थे और अवैध लोगों को भारत में प्रवेश करने से क्यों नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, शाह हमें बता रहे हैं कि तीन करोड़ मतदाता घुसपैठिए हैं। वह इतने वर्षों तक गृह मंत्री रहते हुए क्या कर रहे थे? उन्होंने अवैध लोगों को भारत में प्रवेश करने दिया? उन्हें अपनी अक्षमता के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए। खड़गे ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग ने बार-बार अपना रुख बदला है। उन्होंने कहा, 'एसआईआर पर चुनाव आयोग ने पांच बार यू-टर्न लिया है। इसमें फॉर्म-6 में पूरी तरह बदलाव भी शामिल है, जिसे साथी चुनाव आयुक्तों ने ही 'अवैध' बताया था। ऐसा क्यों? संसद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए खड़गे ने कहा कि संसद के पिछले सत्र को 83 दिनों से अधिक समय बीतने के बावजूद अभी तक सत्रावसान नहीं किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की हालिया गतिविधियों के बाद सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। खरगे ने कहा, संसद के पिछले सत्र का 83 दिनों से अधिक समय बीतने के बाद भी सत्रावसान नहीं हुआ है। अब जब अगला सत्र करीब है, तो वे विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग की पहल और रामलीला मैदान में हुई विशाल 'वोट बचाओ' रैली ने मोदी जी और शाह को परेशान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें सवालों का सामना करना चाहिए और संसद में आकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'आप संसद में नहीं आते। आपने एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अब बहस का समय है। आगे आइए और सवालों का सामना कीजिए। देश को बताइए कि आपने वोट चोरी क्यों की। खड़गे की यह टिप्पणी राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी प्रभाव और देश की वित्तीय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों सहित विभिन्न विषयों पर खुली बहस की चुनौती दिए जाने के एक दिन बाद आई है। मंगलवार को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा था कि वह चर्चा के लिए कोई भी जगह चुन सकते हैं।

उन्होंने विपक्ष को राष्ट्रविरोधी बताने वाले सरकार के आरोपों पर भी सवाल उठाए थे। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर संस्थाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चुनौती देने के बजाय राहुल गांधी को संसद में बहस में हिस्सा लेना चाहिए। सीतारमण ने गृह मंत्री अमित शाह की उस पेशकश का भी जिक्र किया, जिसमें एसआईआर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की बात कही गई थी। उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी संसद में बहस को लेकर वैसा ही उत्साह क्यों नहीं दिखा रहे हैं।

'आत्मज्ञान से मनुष्य को आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है', पीएम मोदी ने साझा किया सुभाषित

नई दिल्ली (एजेंसी)



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषित साझा किया गया है। जिसमें अनुभव और ज्ञान के माध्यम से परम शांति का संदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री की ओर से संस्कृत श्लोक, 'प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतमा' साझा किया गया है, जिसका हिंदी भावार्थ है कि आत्मज्ञान से मनुष्य को आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास मिलते हैं, जो उसे मानसिक तनाव से मुक्त करते हैं।

अपने अनुभव से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है और यही ज्ञान मनुष्य को परम शांति तथा अमरत्व की ओर ले जाता है। पीएम मोदी की ओर से साझा किया गया यह श्लोक केनोपनिषद के तृतीय खंड के द्वितीय अध्याय का चौथा मंत्र है। केनोपनिषद सामवेदीय शाखा का एक प्रमुख उपनिषद है। इस उपनिषद में ब्रह्म (परम सत्य) के स्वरूप पर चर्चा की गई है। इसमें यह समझाया गया है कि ब्रह्म को संसार की सामान्य वस्तुओं या इंद्रियों के विषयों की तरह नहीं जाना जा सकता, बल्कि वह हमारी हर चेतना और आंतरिक बोध का आधार है। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि ब्रह्म कोई बाहर की वस्तु नहीं है जिसे कहीं खोजा जाए; बल्कि हमारे भीतर होने वाले प्रत्येक ज्ञान, विचार और चेतना के हर स्तर पर जो द्रष्ट्य या साक्षी के रूप में विद्यमान है, वही सच्चा ब्रह्म है। जब व्यक्ति को हर अनुभूति में उस परम सत्य का बोध होता है, तब वह अज्ञान और मृत्यु (संसार-चक्र) से मुक्त हो जाता है। इसके माध्यम से बताया गया है कि संसार में मिलने वाली भौतिक वस्तुएं, पद या धन से प्राप्त बल नाशवान होता है। वास्तविक और अटूट आध्यात्मिक शक्ति केवल अपनी आत्मा को पहचानने से ही मिलती है।

छठ पूजा को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट, यमुना घाट का अधिकारियों ने किया निरीक्षण

नोएडा (एजेंसी)



आगामी छठ पूजा पर्व को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने तैयारियां तेज कर दी हैं। छठ पूजा के दौरान यमुना घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में बुधवार को थाना सेक्टर-126 क्षेत्रांतर्गत स्थित यमुना घाट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और आवागमन से जुड़ी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण डीसीपी नोएडा प्रीति यादव के पर्यवेक्षण में किया गया। एडीसीपी नोएडा अभय कुमार मिश्र और एसीपी-1 नोएडा प्रवीण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घाट के आसपास की स्थिति का निरीक्षण करते हुए छठ पूजा के दौरान संभावित भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि छठ पूजा के दौरान घाट पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। घाट तक पहुंचने और वहां से वापस लौटने के दौरान आवागमन सुगम बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध किए जाएं। साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने, किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने और पूरे आयोजन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि छठ पूजा शुरू होने से पहले सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम समय से पूरे कर लिए जाएं। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अपने निर्धारित स्थानों पर मुस्तैद रहें और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। किसी भी आपात स्थिति या अव्यवस्था की आशंका पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी पुलिसबल को तैयार रहने को कहा गया। गौरतलब है कि छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना घाटों पर पहुंचकर अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में घाटों पर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और सुचारु आवागमन की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्रशांत भूषण पर FIR के बाद रिजिजू का हमला, बताया- भारत की छवि और संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तीखा बयान पोस्ट किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'पहले भी इस प्रशांत भूषण ने एक फर्जी खबर फैलाई थी कि जज और मंत्री लंदन बैडमिंटन खेलने गए हैं। और उन्होंने इसके लिए माफी भी नहीं मांगी थी।

यह भारत की छवि और भारत की संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने की साजिश का हिस्सा है।' बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का डिजिटल रूप से फर्जी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने 'एक्स' पोस्ट के जरिए बताया है कि 3 नवंबर को साइबर पेट्रोलिंग के दौरान यह बात सामने आई कि एक सोशल मीडिया हैंडल ने दावा किया था कि प्रशांत भूषण के हैंडल से रूस के विदेश मंत्री का भारत विरोधी फर्जी वीडियो शेयर किया गया है। आरोप है कि इस वीडियो के जरिए भ्रामक, मानहानिकारक और भड़काऊ सामग्री फैलाकर सार्वजनिक उपद्रव और अफवाहें फैलाई गईं। इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि भूषण ने भारतीय विदेश नीति पर आलोचनात्मक टिप्पणी के साथ यह बदलाव किया गया क्लिप शेयर किया था।

रामलीला मैदान में आयोजित रैली से गैरहाजिर रहे पदाधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस का एक्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन की ओर से बुलाई गई 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली में गैरहाजिर रहे पदाधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है। पदाधिकारियों को गैरमौजूदगी भारी पड़ी है। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से तीन राज्यों में बड़ा एक्शन लिया गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 60, हरियाणा में 10 और हिमाचल प्रदेश में 13 युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित कुल 83 लोगों को निलंबित कर दिया है। कांग्रेस की ओर से की गई इस कार्रवाई में प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव से लेकर जिलाध्यक्ष तक के नेता शामिल हैं। रैली में भीड़ जुटाने के दावों के बीच अब संगठन के भीतर ही जवाबदेही तय करने का संदेश दिया जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की रैली को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए कहा था कि ज्ञानेश कुमार को इसके लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जेल जाना होगा। राहुल गांधी ने कहा था कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ज्ञानेश कुमार ने जो किया है, वह सामान्य चोरी नहीं, बल्कि कानूनी भाषा में 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (दुर्लभतम) श्रेणी का मामला है।

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर ईवीएम के इस्तेमाल और मतदाता सूची से 13.5 करोड़ नाम हटाने के जरिए वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए ज्ञानेश कुमार ने जो किया है, वह देशद्रोह और हर नागरिक की आवाज की चोरी के समान है। राहुल गांधी ने कहा था कि यहां जुटे लोग संदेश दे रहे हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली और अमीर क्यों न हो, वह संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने इस रैली को लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुटता और सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देश की आत्मा, लोकतंत्र और संविधान पर हमला किया है, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

ओपन चैलेंज, संसद में आइए, बहस करते हैं! , सीएम रेखा गुप्ता ने दी राहुल गांधी को संसद में बहस करने की चुनौती

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में बहस करने की खुली चुनौती दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को चुनौती दी है। रेखा गुप्ता की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा गया, 'राहुल गांधी जी, ओपन चैलेंज। संसद में आइए। बहस करते हैं! 1975 में आपकी दादी ने इमरजेंसी लगाई। विपक्ष को जेल में डाला। प्रेस का मुँह बंद कर दिया।

लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। 1984 में आपके पिता प्रधानमंत्री थे, जब दिल्ली में हजारों बेगुनाह सिखों का कत्लेआम हुआ था। कांग्रेस आज भी उस खून से सनी विरासत से बच नहीं पाई है।' दिल्ली की सीएम ने एक्स पोस्ट में आगे लिखा, 2014, 2019 और 2024–लगातार तीन टर्म। चौथा टर्म तो आपका सबसे बड़ा बुरा सपना है। भागना मत! जगह भारत की संसद, नई दिल्ली। वीजा की जरूरत नहीं। रेखा गुप्ता की ओर से राहुल गांधी को संसद में बहस की चुनौती तब दी गई, जब उन्होंने मंगलवार की शाम को प्रधानमंत्री को डिबेट करने का चैलेंज किया था। राहुल गांधी के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए दिल्ली की सीएम ने संसद में उनसे बहस करने की चुनौती दे दी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, 24 घंटे हो गए, मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हैं कि विपक्ष देशद्रोही है।

किसी भी स्टेज पर आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ। देशद्रोही कौन है? विदेशी ताकतों का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत। दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठेंगे, एक साइड मैं बैठूंगा। जिसको आप जज बनाना चाहते हैं, बना दीजिए। मोहन भागवत जी को बिठा दीजिए, चलिए। और फिर डिबेट करते हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा था, सवाल उठेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, यूएस डील कैसे हुई, क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, एपस्टीन- ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिन पर खुलकर डिस्कशन होगा। आ जाइए, डरिए मत। दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। आप एलिगेशन लगाते हैं न मेरे ऊपर, आ जाइए, सब साफ हो जाएगा। कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'बाकी चीजों पर आपने मानहानि का केस लगा रखा है, शायद 45 मानहानि के केस मेरे ऊपर हैं। मगर इस डिबेट के मामले में, विदेशी कनेक्शन पर आप मानहानि नहीं लगा रहे हैं। लगाइए न, वहां भी डिस्कस करेंगे, खुलकर। ये सब डिस्कस करते हैं, आइए। हैप्पी दीपावली।

मौसम : दिल्ली-नोएडा-गाजियाबाद में एक्यूआई 450 के पार, सड़कों की धूल बनी मुसीबत

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। दिन की तुलना में अब रातें ठंडी होने लगी हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन हवा की गुणवत्ता ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली के कई इलाकों में 400 और 450 के पार पहुंच गया है, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक्यूआई 450 दर्ज किया गया। वहीं, आईआईटी दिल्ली में 453, अलीपुर में 422, आईटीओ में 421 और बवाना में 411 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा आनंद विहार (302), अशोक विहार (348), आया नगर (382), बुराड़ी क्रॉसिंग (393) और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (411) जैसे इलाकों में भी हवा की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक है। नोएडा के सेक्टर-62 में एक्यूआई 426 तक पहुंच गया है, जबकि सेक्टर-150 में 351, सेक्टर-110 में 349 और सेक्टर-39 में 321 एक्यूआई दर्ज किया गया। हालांकि, सेक्टर-125 (243) और सेक्टर-116 (261) में हवा कुछ राहत देने वाली है, लेकिन यह अभी भी 'खराब' श्रेणी में ही है।

गाजियाबाद की बात करें तो यहां के लोनी में एक्यूआई 304, संजय नगर में 308 और वेव सिटी में 312 दर्ज किया गया। नोएडा में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के पीछे एक बड़ी वजह सड़क निर्माण का कार्य भी है। शहर के कई इलाकों में अभी भी सड़क निर्माण से जुड़े कार्य जारी हैं, जिससे सड़कें धूल से पटी हुई हैं। उड़ती हुई यह धूल हवा में घुलकर एक्यूआई को और अधिक खराब कर रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए न तो नोएडा प्राधिकरण और न ही नोएडा पीसीबी (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आईएमडी के डेटा के अनुसार, 4 नवंबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री रहेगा।

5 और 6 नवंबर को तापमान 29 डिग्री तक जा सकता है। वहीं, 7 नवंबर से फिर से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पर आ जाएगा। 9 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। एनसीआर के लोग इस समय जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं।

रूसी विदेश मंत्री का 'फर्जी' वीडियो शेयर करने पर प्रशांत भूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कथित रूप से डॉक्टर्ड वीडियो शेयर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह मामला मंगलवार (3 नवंबर) को साइबर पेट्रोलिंग के दौरान सामने आया। टीम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रूसी विदेश मंत्री का कथित तौर पर छेड़छाड़ किया गया वीडियो भूषण के हैंडल से शेयर किया गया था। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, 3 नवंबर को, साइबर पेट्रोलिंग के दौरान, यह पता चला कि एक सोशल मीडिया हैंडल ने दावा किया है कि रूसी विदेश मंत्री का एक कथित डॉक्टर्ड वीडियो, जो भारत के खिलाफ है, प्रशांत भूषण के हैंडल से शेयर किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा, 'वीडियो के माध्यम से भ्रामक, मानहानिकारक और भड़काऊ सामग्री प्रसारित कर सार्वजनिक उपद्रव व अफवाहें फैलाने का आरोप है।

इस संबंध में बीएनएस की धारा 336(4), 353(1) (सी), 356 और 340(2) के तहत एफआईआर और आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है।' अधिकारियों ने बताया कि यह एफआईआर स्पेशल सेल पुलिस थाने में दर्ज की गई है। इससे पहले, विदेश मंत्रालय (एमईए) की फैक्ट-चेक यूनिट ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के कथित वीडियो के संबंध में बयान दिया और इसे फर्जी बताया। शेयर किए गए डॉक्टर्ड वीडियो में रूसी विदेश मंत्री भारत के अंदरूनी मामलों और तेल खरीद पर आलोचना करते हुए दिख रहे थे। प्रशांत भूषण की ओर से शेयर किए गए वीडियो के तथ्यों को रूसी दूतावास ने भी खारिज किया था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि क्लिप पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। एमईए ने एक पोस्ट में लिखा, 'फेक अलर्ट! इस पोस्ट में इस्तेमाल किया जा रहा रूसी विदेश मंत्री का वीडियो फर्जी है!

'मस्जिद से एलर्जी है', कदीमी मस्जिद मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना

नई दिल्ली (एजेंसी)



असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के रीडेवलपमेंट के लिए नई दिल्ली में कृषि भवन कंपाउंड में मौजूद 100 वर्ष पुरानी कदीमी मस्जिद को हटाना होगा

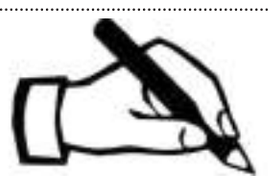
एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नई दिल्ली में कृषि भवन कंपाउंड में मौजूद सौ साल पुरानी कदीमी मस्जिद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसे मस्जिद से एलर्जी है।

असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) के रीडेवलपमेंट के लिए नई दिल्ली में कृषि भवन कंपाउंड में मौजूद 100 वर्ष पुरानी कदीमी मस्जिद को हटाना होगा। सरकार का तर्क है कि मस्जिद 'नाजायज है और सरकारी प्रॉपर्टी के सेक्युलर नेचर के साथ मेल नहीं खाती'। मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन भूमि पूजा के साथ किया। साफ है, सेक्युलरिज्म को किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए एक धर्म के रीति-रिवाजों के इस्तेमाल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे एक ऐसी मस्जिद से एलर्जी है जो 1912 से भी पहले से, कृषि भवन के बनने से बहुत पहले से वहां मौजूद है।' सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।

अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि कृषि भवन में मौजूद मस्जिद सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है और इसे हटाया जाना चाहिए। बीते दिन केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कृषि भवन परिसर में स्थित कदीमी मस्जिद को हटाने की जरूरत है, ताकि सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट मास्टर प्लान के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग 4 और 5 का पुनर्विकास हो सके। सरकार का कहना है कि यह निर्माण राष्ट्रीय महत्व की सर्वोपरि जन परियोजना है और प्रोजेक्ट साइट पर फिलहाल मस्जिद मौजूद होने से इसके कार्यान्वयन में बाधा आ रही है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने स्पष्ट तर्क दिया है कि किसी भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर की सीमा के भीतर स्थायी धार्मिक ढांचा स्थापित करना, बनाए रखना या दावा करना अस्वीकार्य है और यह सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विपरीत है। सरकार ने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में स्थित सार्वजनिक भूमि पर कोई स्थायी धार्मिक निर्माण नहीं हो सकता।

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि कृषि भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक परिसर हैं, जो विशेष रूप से सरकारी, प्रशासनिक और जनसेवा कार्यों के लिए समर्पित हैं। ऐसे में परिसर के भीतर धार्मिक ढांचे को बनाए रखना उचित नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि सीसीएस बिल्डिंग 4 और 5 का निर्माण सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान का अहम हिस्सा है।

सम्पादकीय



अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षा और सम्मान की नई राह

भारतीय सेना किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की सबसे मजबूत आधारशिला होती है। सेना की शक्ति केवल आधुनिक हथियारों और सैन्य संसाधनों से नहीं, बल्कि उसके जवानों के साहस, अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति से निर्धारित होती है। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भारतीय सेना को आधुनिक, युवा और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत अग्निवीरों की चार वर्ष की सेवा निर्धारित की गई है, जिसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल करने का प्रावधान है। ऐसे में मौजूदा बैचों के सभी अग्निवीरों को स्थायी सैनिक बनने का अवसर देने की दिशा में उठाया गया कदम लाखों युवाओं की उम्मीदों को नई मजबूती दे सकता है।

अग्निपथ योजना की शुरुआत से ही इसके पक्ष और विपक्ष में अलग-अलग विचार सामने आते रहे हैं। सरकार का तर्क रहा है कि इस व्यवस्था से सेना की औसत आयु कम होगी, सैन्य बल अधिक युवा और ऊर्जावान बनेगा तथा रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के अनुरूप बदलाव लाने में मदद मिलेगी। वहीं, युवाओं के बीच चार वर्ष की सेवा के बाद भविष्य की अनिश्चितता को लेकर चिंताएं भी रही हैं। विशेष रूप से उन अग्निवीरों के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण रहा है, जिन्होंने पूरी निष्ठा और मेहनत से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और देश की सुरक्षा में अपना योगदान दिया है।

यदि मौजूदा बैचों के सभी अग्निवीरों को स्थायी सैनिक बनने का अवसर मिलता है तो यह उनके लिए केवल रोजगार की सुरक्षा नहीं, बल्कि उनके सैन्य समर्पण और सेवा भावना का सम्मान भी होगा। सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए वर्दी पहनना किसी सामान्य नौकरी की तरह नहीं होता, बल्कि यह राष्ट्रसेवा का संकल्प होता है। प्रशिक्षण के दौरान वे कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं, अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं और देश की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने की तैयारी करते हैं। ऐसे में उनकी सेवाओं और अनुभवों का बेहतर उपयोग करना राष्ट्रीय हित में भी महत्वपूर्ण है।

हालांकि, स्थायी नियुक्ति से संबंधित किसी भी निर्णय को लागू करते समय सेना की परिचालन आवश्यकताओं, वित्तीय संसाधनों, प्रशिक्षण व्यवस्था और मानव संसाधन नीति को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। सेना में जवानों की संख्या और संरचना का निर्धारण केवल रोजगार उपलब्ध कराने के आधार पर नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही, चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तथा स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि किसी भी अग्निवीर के मन में भेदभाव या अनिश्चितता की भावना न रहे। यह भी जरूरी है कि जो अग्निवीर नियमित सैनिक बनने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते, उनके भविष्य को लेकर भी सरकार ठोस व्यवस्था करे।

त्योहारों पर उमड़ती प्रवासियों की भीड़

कांतिलाल मांडोत

औद्योगिक नगरी सूरत में रोजगार के लिए उत्तर भारत और राजस्थान के लाखों लोग बसे हैं। कपड़ा, हीरा और निर्माण कारोबार में काम करने वाले परिवारों के लिए दीपावली और छठ पूजा अपनी मिट्टी और परिवार से जुड़ने का अवसर हैं। नवरात्रि से ही गांव लौटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। त्योहारों के आसपास उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। इस वर्ष उधना स्टेशन पर उमड़ी भीड़ ने रेल सेवाओं और यात्रियों की जरूरत के बीच का अंतर फिर सामने रख दिया।

शनिवार देर शाम स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगी। स्थिति संभालने के लिए मंडल रेल प्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारी रात में पहुंचे। रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस के जवानों ने यात्रियों को कतारों में लगवाया। करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से 13 हजार वर्गमीटर में बने यात्री होल्डिंग एरिया को भी खोल दिया गया। बैरिकेडिंग कर प्रवेश की व्यवस्था की गई। भीड़ का दबाव इतना था कि कुछ समय बाद फिर कतारें बनवानी पड़ीं।

यात्रियों की सुविधा के लिए उधना से छह अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाई गईं। इनके साथ तीन नियमित ट्रेनों से भी यात्रियों को रवाना किया गया। तड़के करीब 3.30 बजे अतिरिक्त विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन सेवाओं से 25 हजार से अधिक यात्री रवाना हुए। यह संख्या बताती है कि त्योहारों में सूरत से घर जाने वालों की जरूरत कितनी बड़ी है। अतिरिक्त ट्रेनों से राहत मिली, लेकिन हर साल लौटने वाली भीड़ के लिए स्थायी रेल योजना जरूरी है।

उधना-जयनगर सहित उत्तर भारत की ट्रेनों में जगह की कमी से यात्रियों को परेशानी हुई। कई परिवारों ने भीड़ देखकर ट्रेन में चढ़ने के बजाय प्लेटफॉर्म पर इंतजार किया। बच्चों और सामान के साथ सफर करने वालों के लिए स्थिति कठिन रही। जयनगर, मुगलसराय और अन्य गंतव्यों के यात्रियों को जगह पाने के लिए जूझना पड़ा। विशेष ट्रेनें तत्काल राहत देती हैं, लेकिन पर्याप्त डिब्बे और नियमित सेवाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

होल्डिंग एरिया का निर्माण और उसका उपयोग स्वागतयोग्य कदम है। अब यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश से पहले कतारबद्ध करने की सुविधा बनी है। पत्रिका ने पहले भी यात्रियों की संख्या और उपलब्ध व्यवस्था के अंतर को उजागर किया था। इसके बाद रेलवे ने सुधार के निर्देश दिए। समस्याओं को सामने लाने से बदलाव संभव है। हालांकि स्टेशन परिसर व्यवस्थित करना ही पर्याप्त नहीं। मूल समाधान पर्याप्त ट्रेनें, अतिरिक्त कोच और समयबद्ध संचालन है। इस समस्या का अहम पक्ष राजस्थान के प्रवासी यात्रियों से जुड़ा है। सूरत, मुंबई और गुजरात के अन्य शहरों में मेवाड़ सहित राजस्थान के लाखों लोग रहते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जाने वालों को कई बार सीधी रेल सुविधा नहीं मिलती। उन्हें दूसरे शहरों में उतरकर बस या निजी वाहन से यात्रा करनी पड़ती है। त्योहारों में निजी बसों पर निर्भरता और किराया दोनों बढ़ जाते हैं। परिवार के साथ सफर करने वाले श्रमिकों और मध्यमवर्गीय यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।

सूरत से उदयपुर के लिए वंदे भारत सेवा शुरू होना पहल है, लेकिन जरूरत केवल एक तेज ट्रेन से पूरी नहीं होती। प्रवासी समुदाय की मांग है कि मुंबई से उदयपुर के बीच प्रतिदिन दो नियमित ट्रेनें चलाई जाएं। इससे मुंबई, सूरत और गुजरात के अन्य शहरों से राजस्थान जाने वालों को विकल्प मिलेगा।

आपसी सहमति

लोग धरना प्रदर्शन करते हैं लोग अपनी बात को मनवाने के लिए सामने वाले को नीचा भी दिखाते हैं फिर लोग सोचते हैं कि सामने वाला मुझे इज़्ज़त दे और मेरी बातों को समझे अगर एक तरफा लोग सोच कर इस तरीके की सोच रखकर अपने को चोट पहुंचाएंगे तो गलत सामने वाला कैसे आपको सही समझ सकता है इसलिए कहा जाता है। व्यक्ति को अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करने से पहले आपसी सहमति वाली चर्चा करनी चाहिए।



करिश्मा गुज्जर (खारी)

दिल्ली से मुंबई तक : हवा और हुकूमत का संघर्ष

सचिन कुमार गौतम

केंद्र में नरेन्द्र मोदी के बारह साल के शासन का एक गंभीर परिणाम यह है कि सामान्य बुद्धि को ताक पर रखकर धर्म के नाम पर खुद को नुकसान पहुँचाने से लोग अब झिझकने लगे हैं। यह बात विशेष रूप से तब सामने आती है जब देश दीपावली जैसे पर्व की तैयारी कर रहा हो। फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला यह उत्सव आज प्रदूषण की कालिमा से घिर चुका है। बरसों से दीपावली के पहले और बाद वायु तथा ध्वनि प्रदूषण चिंता का बड़ा विषय बन चुका है। दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में हवा ऐसी हो चुकी है कि उसमें साँस लेना भी खतरनाक हो गया है।

पहले पानी को इतना प्रदूषित कर दिया गया कि वॉटर प्यूरीफायर अब अनिवार्य उपकरण बन गए हैं। हर संपन्न घर में उसे पाया जा सकता है, जहाँ नहीं है वहाँ बोतलबंद पानी खरीदा जाता है। लेकिन गरीबों के लिए यह अब भी विलासिता है। उनके घरों में नल तक नहीं होता; वे नगर निगम के नलों, तालाबों या कुओं से पानी भरते हैं और कई जगहों पर दूर-दराज से पानी ढोकर लाते हैं। ऐसे में उस पानी को शुद्ध करने की बात तो और भी दूर की है।

पानी के बाद अब हमला हवा पर हुआ है। प्रकृति के अनमोल उपहार–हवा और पानी–धीरे-धीरे अमीरों के निजी संसाधन बनते जा रहे हैं। हवा को अभी बोतल में बंद करके नहीं बेचा जा रहा, पर एयर प्यूरीफायर तेजी से बिक रहे हैं। जिन घरों में यह नहीं है, वहाँ लोग पौधों से हवा शुद्ध करने की कोशिश करते हैं या मास्क पहनते हैं। कोविड काल ने मास्क पहनना सिखाया था, अब वह प्रदूषण से बचाव का साधन बन गया है। पर गरीबों के लिए यह भी एक विलासिता ही है।

भारत में पूँजीवाद का ऐसा चेहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी कल्पना शायद उसके कट्टर समर्थकों ने भी नहीं की होगी–कि गरीबों और असहायों से उनके जीने के मूल आधार, यानी हवा और पानी, ही छिन लिए जाएँ। यह अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है कि देश के कई शहरों की हवा अब साँस लेने लायक नहीं रह गई है।

प्रदूषण की नियति

वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई में दो सौ, तीन सौ के आँकड़े पार करना अब मामूली बात मानी जाने लगी है, जबकि यह प्राणवायु नहीं, जहरीली हवा होती है। हर साल अक्टूबर से दिसंबर-जनवरी तक यही हालात



बने रहते हैं। दिल्ली के आसपास पराली जलाने को लंबे समय तक प्रदूषण का प्रमुख कारण बताया जाता रहा। पर जब पराली नहीं जलती, तब भी आकाश में धुएँ और धुंध की मोटी परत दिखती है। इसके ऊपर पटाखों से हालात और गंभीर हो जाते हैं। प्रदूषण के प्रभाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर भारत में सूक्ष्म प्रदूषकों का स्तर मानकों तक घटाया जा सके, तो दिल्ली-एनसीआर के निवासियों की जीवन प्रत्याशा में आठ साल से अधिक की वृद्धि हो सकती है। यानी दूषित हवा केवल असुविधा नहीं, जीवन को छोटा करने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है।

कायदे से समाज को ही पहल करनी चाहिए कि वह स्वच्छ वायु बनाए रखने में अपना योगदान दे। दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की जीत का पर्व है। दीये जलाना, मिठाई बाँटना, परिवार से मिलना और नई उम्मीदें जोड़ना इसका सार है। पर जब वही पर्व धधकते पटाखों, जहरीले धुएँ और भयंकर शोर में बदल जाए, तो उसका मूल अर्थ ही संकट में पड़ जाता है। समस्या यह है कि इस मुद्दे को भी धर्म और राजनीति से जोड़ दिया गया है। मानो हिंदुत्व की माला जपने वालों को शुद्ध हवा मिलेगी और बाकी लोग दमघोंटू माहौल में रहने के लिए अभिशप्त हैं। जबकि हवा किसी की निजी संपत्ति नहीं है। वह अमीर-गरीब, सत्ताधारी-विपक्ष, धार्मिक-अधार्मिक सबके फेफड़ों में समान रूप से प्रवेश करती है।

दिल्ली का उलटा रुख

नौबत यहाँ तक आ गई है कि पुलिस भी दबाव में दिखने लगी है। बीते 25 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने 'नो टू क्रैकर्स, यस टू ग्रीनर दीवाली' के नाम से एक संदेश पोस्ट किया था, जिसमें पटाखों से परहेज़ और हरित दिवाली की अपील की गई थी। पर कुछ ही घंटों में उसे सोशल मीडिया हैंडल से हटा लिया गया। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली प्रशासन ने दीपावली के दौरान पटाखों को लेकर अपना रुख बदला हो।

2024 की दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध के कमजोर क्रियान्वयन की आलोचना की और उसे स्थायी बनाने पर विचार करने का सुझाव दिया। दिसंबर 2024 में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने पटाखों पर साल भर का प्रतिबंध लगा दिया है।

पर स्थिति जल्दी बदल गई। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध में ढील देने से मना किया, लेकिन अक्टूबर में उसने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के अवसर पर प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की सीमित अनुमति दे दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये पटाखे नीरी के तय मानकों को पूरा करें, लाइसेंसी विक्रेताओं के माध्यम से ही बिकें और केवल निर्धारित समय में ही जलाए जाएँ। दिल्ली सरकार और केंद्र ने इस ढील का समर्थन किया।

उस समय शहर का एक्यूआई लगभग 500 तक पहुँच गया था, जो गैस चैंबर जैसा खतरनाक स्तर था। अब भी हालात उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। इस साल भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तक तथा रात 8 से 10 बजे तक केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है; 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू होगा। अस्पतालों, नर्सिंग होमों और निर्धारित साइलेंस ज़ोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाना प्रतिबंधित रहेगा।

सवाल यह है कि जब वैज्ञानिक आँकड़े, न्यायालय के निर्देश और स्वास्थ्य की चेतावनियाँ एक ही दिशा में हों, तो सत्ता क्यों हर बार 'परंपरा' के नाम पर पीछे हटती है? परंपरा का सम्मान जरूरी है, पर परंपरा का अर्थ जनता की सेहत को दाँव पर लगाना नहीं हो सकता।

मुंबई का विवाद

यही तनाव मुंबई में भी देखने को मिला। वहाँ हवा खराब हो चुकी है और बॉम्बे हाईकोर्ट तथा बृहन्मुंबई नगर निगम ने पर्यावरण-अनुकूल दीपावली मनाने की मुहिम शुरू की। इसके तहत कुछ चर्चित हस्तियों से जागरूकता वीडियो बनवाए गए। दीया मिर्जा, माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे इसमें शामिल थे।

गिग वर्कर्स की सुरक्षा का सवाल

डॉ. सत्यवान सौरभ

बदलती अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्वरूप तेजी से बदल रहे हैं। डिजिटल तकनीक और इंटरनेट आधारित सेवाओं ने काम करने के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दी है। आज कोई व्यक्ति मोबाइल एप के माध्यम से भोजन पहुँचाकर, ऑनलाइन टैक्सी चलाकर, सामान की डिलीवरी करके, घरेलू सेवाएँ उपलब्ध कराकर या स्वतंत्र डिजिटल कार्य करके अपनी आजीविका अर्जित कर सकता है। रोजगार का यह स्वरूप गिग इकोनॉमी कहलाता है और इसमें काम करने वाले लोग गिग वर्कर्स के रूप में पहचाने जाते हैं। इन श्रमिकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सुविधा और उपलब्धता के अनुसार काम चुन सकते हैं, लेकिन इस लचीलेपन के साथ उनकी आजीविका में असुरक्षा भी जुड़ी हुई है। नियमित कर्मचारियों की तरह उन्हें वेतन, भविष्य निधि, पेंशन, चिकित्सा सुविधा और सवेतन अवकाश जैसी सुविधाएँ सामान्यतः उपलब्ध नहीं होतीं। इसलिए गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा अब केवल श्रम कल्याण का विषय नहीं, बल्कि समावेशी विकास और आर्थिक न्याय की अनिवार्य शर्त बन गई है।

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने गिग रोजगार को नई गति दी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, देश में गिग वर्कर्स की संख्या वर्ष 2029-30 तक लगभग 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। यह संख्या बताती है कि आने वाले समय में रोजगार का यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। भोजन की आपूर्ति, परिवहन, ई-कॉमर्स, घरेलू सेवाओं और विभिन्न डिजिटल मंचों पर काम करने वाले लाखों लोग शहरों की आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई है। एक डिलीवरी कर्मी सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाए तो उसकी आमदनी तत्काल बंद हो सकती है।

बीमारी के कारण कई दिन काम न कर पाने पर परिवार का खर्च चलाना कठिन हो जाता है। महिलाओं के सामने मातृत्व अवकाश और आय की निरंतरता जैसी चुनौतियाँ हैं। वृद्धावस्था में नियमित पेंशन का अभाव उनकी चिंता को और बढ़ा देता है। सामाजिक सुरक्षा का मूल उद्देश्य श्रमिकों को जीवन की अनिश्चित परिस्थितियों में आर्थिक सहारा देना है। गिग वर्कर्स के संदर्भ में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी आय काम की उपलब्धता, ग्राहकों की माँग, मौसम, मंचों की नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं पर निर्भर करती है।

कई बार मंचों द्वारा भुगतान की दरों में बदलाव या प्रोत्साहन राशि में कटौती से उनकी वास्तविक आय प्रभावित होती है। ऐसे में दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था पेंशन जैसी सुविधाएँ उन्हें आर्थिक संकट से बचा सकती हैं। सामाजिक सुरक्षा का लाभ केवल श्रमिक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। इससे गरीबी, असमानता और आर्थिक अस्थिरता को कम करने में भी सहायता मिलती है।

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अलग श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई है। इस संहिता के अंतर्गत उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ बनाने और लागू करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं का उद्देश्य श्रमिकों, एग्रीगेटर्स और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना तथा कल्याणकारी योजनाओं की दिशा तय करना है। 22 सदस्यीय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी का प्रावधान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे बोर्ड केवल योजनाओं की अनुशंसा करने वाली संस्थाएँ न बनें, बल्कि श्रमिकों की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनके समाधान का प्रभावी माध्यम बनें, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।

इन बोर्डों की भूमिका कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला, वे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण और उनकी प्राथमिकताओं के निर्धारण में योगदान दे सकते हैं। दूसरा, वे जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, दिव्यांगता सहायता, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था सुरक्षा जैसी सुविधाओं के विस्तार की निगरानी कर सकते हैं। तीसरा, योजनाओं पर होने वाले व्यय और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करके जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। चौथा, वे यह व्यवस्था विकसित करने में मदद कर सकते हैं कि किसी श्रमिक को एक डिजिटल मंच से दूसरे मंच पर जाने या एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने पर उसके सामाजिक सुरक्षा लाभ समाप्त न हों।

ई-श्रम पोर्टल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। आधार से जुड़ा पंजीकरण श्रमिकों की पहचान और उनके कल्याणकारी लाभों की उपलब्धता को सुगम बना सकता है। हालांकि केवल पंजीकरण कर देना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक सफलता तब होगी, जब पंजीकृत श्रमिक को समय पर दुर्घटना सहायता, बीमा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य निर्धारित लाभों का भुगतान भी मिले। इसके लिए डिजिटल व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और श्रमिकों के अनुकूल बनाना होगा। हालाँकि इस व्यवस्था के सामने कई गंभीर चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी समस्या रोजगार संबंधों की अस्पष्टता है। गिग वर्कर्स को अक्सर स्वतंत्र साझेदार या सेवा प्रदाता माना जाता है, जबकि उनके काम की शर्तें, भुगतान, कार्य आवंटन और प्रदर्शन का मूल्यांकन डिजिटल मंचों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऐसे में यह तय करना कठिन हो जाता है कि सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। दूसरी समस्या योजनाओं और वास्तविक लाभों के बीच अंतर है। कई श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी नहीं होती, तो कुछ के लिए पंजीकरण और दावा प्रक्रिया जटिल होती है। तीसरी चुनौती श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की है। यदि नीतिगत निर्णयों में उनकी वास्तविक भागीदारी नहीं होगी, तो योजनाएँ जमीनी जरूरतों के अनुरूप नहीं बन पाएँगी।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी एक बड़ा प्रश्न है। सामाजिक सुरक्षा संहिता में एग्रीगेटर्स के योगदान का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत उनके वार्षिक कारोबार के एक से दो प्रतिशत तक योगदान की व्यवस्था निर्धारित की गई है, जो श्रमिकों को किए गए भुगतान की कुल राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। इस व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के लिए स्थायी वित्तीय आधार तैयार करना है। लेकिन योगदान की गणना, संग्रह और उपयोग में पारदर्शिता आवश्यक है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका आर्थिक बोझ किसी अप्रत्यक्ष तरीके से श्रमिकों की आय पर न डाला जाए।

आगे की राह स्पष्ट है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक गिग वर्कर का सरल पंजीकरण, विभिन्न मंचों पर पोर्टेबल लाभ, नियमित सामाजिक सुरक्षा अंकेक्षण और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी होगी। महिला श्रमिकों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मातृत्व सहायता और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा बोर्डों में श्रमिक प्रतिनिधियों की वास्तविक और पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

संकट पानी का नहीं, उसके उचित प्रबंधन का है

मन्जू, लूणकरणसर, राजस्थान

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी का मौसम केवल तापमान बढ़ने का समय नहीं होता, बल्कि यह पानी की उपलब्धता और उसके प्रबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, गांवों में कुओं, तालाबों और जलाशयों का पानी कम होने लगता है। कई जगह हैंडपंप और नलकूप पर्याप्त पानी नहीं दे पाते। इसका असर केवल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर नहीं पड़ता, बल्कि पशुपालन और खेती भी इससे प्रभावित होते हैं। राजस्थान के लूणकरणसर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी का अर्थ है कि ग्रामीण परिवारों को पीने के पानी से लेकर पशुओं के लिए चारा उगाने तक, हर स्तर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

यहां यह समझना जरूरी है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण असमान है। राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश कम और अनिश्चित होती है। कई बार अच्छी बारिश के बावजूद पानी का बड़ा हिस्सा बहकर निकल जाता है या तेज गर्मी के कारण जल्दी वाष्पित हो जाता है। दूसरी ओर, भूजल पर लगातार बढ़ती निर्भरता ने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के वर्ष 2024 के आकलन के अनुसार, राजस्थान में सालाना भूजल दोहन की दर 148.77 प्रतिशत थी। राज्य की 302 आकलन इकाइयों में से 216 को अत्यधिक दोहन की श्रेणी में रखा गया था। इसका अर्थ है कि जितना भूजल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो रहा है, उससे कहीं अधिक निकाला जा रहा है।इस दिशा में सबसे जरूरी कदम वर्षा जल का संचयन है। राजस्थान में पारंपरिक रूप से पानी जमा करने के कई तरीके प्रचलित रहे हैं। टांका, जोहड़, नाड़ी, खड़ीन, बावड़ी और कुंड जैसी व्यवस्थाएं स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और कम वर्षा को ध्यान में रखकर विकसित की गई थीं। इन परंपरागत संरचनाओं को आधुनिक तकनीक के साथ फिर से मजबूत करने की जरूरत है।

गांवों में घरों की छतों से बारिश का पानी पाइप के माध्यम से टांकों और भूमिगत टंकियों तक पहुंचाया जा सकता है। पंचायत स्तर पर तालाबों की सफाई, गहरीकरण और उनके आसपास जलग्रहण क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। खेतों में छोटे जलाशय और फार्म पॉन्ड बनाकर बारिश के पानी को जमा किया जा सकता है। इससे एक ओर भूजल का पुनर्भरण होगा, वहीं दूसरी ओर गर्मियों में पशुओं और खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

राजस्थान सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किया है। फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत अगले चार वर्षों में राज्य के 20 हजार गांवों में पांच



लाख जल संग्रहण और संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार की 2024-25 की बजट घोषणा में इस अभियान के लिए लगभग 11,200 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया था।

पेयजल उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना भी महत्वपूर्ण है। जुलाई 2026 में प्रकाशित जानकारी के अनुसार राजस्थान के लगभग 1.07 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से करीब 63.64 लाख परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था। यह कुल ग्रामीण परिवारों का लगभग 59.11 प्रतिशत था। राज्य के सामने शेष परिवारों तक कनेक्शन पहुंचाने के साथ जल स्रोतों को टिकाऊ बनाए रखने की चुनौती भी है। खेती में पानी की खपत कम करना भी जल संकट के स्थायी समाधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजस्थान में बड़ी संख्या में किसान सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भर हैं। पारंपरिक तरीके से खेतों में पानी भरकर सिंचाई करने से काफी पानी व्यर्थ चला जाता है। इसके स्थान पर ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए। राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाने के लिए अनुदान दे रही है।

राज्य के आर्थिक समीक्षा दस्तावेज 2025-26 के अनुसार सामान्य किसानों को 70 प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति, महिला, छोटे एवं सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। इसके बावजूद छोटे किसानों तक इन तकनीकों की पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए पंचायत स्तर पर प्रदर्शन खेत विकसित किए जा सकते हैं, जहां किसान इन प्रणालियों को देखकर और समझ कर अपना सकें।

पानी की कमी से जूझ रहे दूसरे राज्यों और देशों के अनुभव भी राजस्थान के लिए उपयोगी हो सकते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का हिवरे बाजार गांव इसका एक अच्छा उदाहरण है। कभी पानी की गंभीर कमी से जूझने वाले इस गांव में ग्रामीणों ने जलग्रहण क्षेत्र का विकास, वर्षा जल संचयन, छोटे बांधों और मिट्टी-पानी संरक्षण के कार्यों को सामुदायिक भागीदारी से आगे बढ़ाया। लगभग 400 मिलीमीटर सालाना बारिश वाले इस गांव ने पांच वर्षों में अपनी जल उपलब्धता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किया। इस बदलाव में सरकारी योजनाओं और पंचायत के संसाधनों के साथ ग्रामीणों की सामूहिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह उदाहरण बताता है कि कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी सही योजना और सामुदायिक प्रयास से पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह इजरायल ने सीमित जल संसाधनों के बावजूद कृषि क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई और शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को व्यापक स्तर पर अपनाया है। वहां शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले गंदे पानी को शोधित करके खेती में इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान में भी शहरों और कस्बों के सीवेज को उचित तकनीक से साफ करके गैर-खाद्य फसलों, बागवानी और औद्योगिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने की संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं। इससे भूजल और मीठे पानी पर निर्भरता कम होगी।

दरअसल, राजस्थान के गांवों में पानी की समस्या का समाधान केवल नए जल स्रोत बनाने में नहीं, बल्कि उपलब्ध पानी को बचाने, जमा करने और जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करने में छिपा है। यदि वर्षा जल संचयन, आधुनिक सिंचाई तकनीक, पारंपरिक जल संरचनाओं के पुनर्जीवन और सामुदायिक भागीदारी को एक साथ आगे बढ़ाया जाए तो स्थिति में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक विजय कुमार द्वारा ओ.एस. पब्लिकेशन, बी-2542, नरेला, इंडस्ट्रियल एरिया, नार्थ वेस्ट दिल्ली-110040 से मुद्रित कराकर 1536/108 गणेशपुरा रोड, त्रीनगर दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय कुमार RNI No. : DELHIN/2015/66886
अखबार में प्रकाशित तथ्यों एवं लेखों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं, किसी भी कानूनी वाद विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय के अधीन होगा। मोबाइल : 9210092542 फोन :- 011-46696546 E-mail : opensearchdelhi@gmail.com

पीएम मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को दिया नया गौरव : सीएम योगी

लखनऊ (एजेंसी)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को नया गौरव दिया है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अयोध्या के दीपोत्सव पर बात की। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में कहा, 'श्री अयोध्या जी का दीपोत्सव आज भारत और विश्व के मध्य एक अद्भुत 'सांस्कृतिक रामसेतु' बन गया है।

श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और थाईलैंड सहित विभिन्न देशों के कलाकार अपनी भाषा और परंपराओं में रामकथा को जीवंत करते हैं। जैसे अनेक नदियां एक ही सागर में मिलती हैं, वैसे ही विभिन्न संस्कृतियों की ये धाराएं श्री अयोध्या जी में आकर एक ही 'रामत्व' में समाहित हो जाती हैं।' सीएम योगी ने कहा, आधुनिक तकनीक इस सांस्कृतिक संगम को और भव्य बनाते हुए नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली विरासत से जोड़ रही है। इसी बीच, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पोस्ट में कहा, 'वर्ष 2017 से पहले सत्ता में बैठे लोगों की सांस्कृतिक सोच सैफई महोत्सव में अपने परिवार का वैभव दिखाने तक सीमित थी। श्री अयोध्या जी की महान विरासत उनकी प्राथमिकता में नहीं थी।' सीएम योगी ने आगे कहा, उनके लिए परिवार ही प्रदेश था, हमारे लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है। उन्होंने कहा कि 'प्रदेश ही परिवार है' की सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने श्री अयोध्या जी की सांस्कृतिक पहचान को नया गौरव दिया है। आज दीपोत्सव सिर्फ दीपों का उत्सव नहीं, बल्कि करोड़ों रामभक्तों की आस्था, आधुनिक तकनीक और भारत की सनातन विरासत का ऐसा संगम है, जिसकी आभा पूरे विश्व तक पहुंच रही है।

बता दें कि दिवाली पर अयोध्या में परंपरागत दीयों की रोशनी के साथ आधुनिक तकनीक का संगम सरयू घाटों पर दृश्य रचा जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से दीपोत्सव के दौरान मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन और लेजर शो के साथ 100 से अधिक कलाकारों का लाइव परफॉर्मेंस होगा। राम की पैड़ी पर 7 नवंबर को होने वाले भव्य आयोजन में दीपों की आभा को कृत्रिम रोशनी, तकनीक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ जोड़कर आगंतुकों के लिए विशेष अनुभव प्रस्तुत करेगा।

7 नवंबर (दीपोत्सव-2026) को मुख्य आयोजन में 100 से अधिक भारतीय लोक और शास्त्रीय कलाकार प्रस्तुति देंगे। सभी कलाकारों की वेशभूषा दीपोत्सव की सांस्कृतिक और थीम आधारित होगी। कहानी, नृत्य, संगीत, वॉयस ओवर और प्रकाश प्रभावों के समन्वय से श्रीराम के अयोध्या आगमन की कथा क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत की जाएगी। हिंदी में तैयार पटकथा को नाटकीय रूप देने की जिम्मेदारी प्रसिद्ध या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त क्रिएटिव डायरेक्टर अथवा स्क्रिप्ट राइटर के निर्देशन में होगी।

'पीएम मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध', : सीएम योगी



भाजपा की ओर से आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा बुधवार को गोरखपुर में आयोजित की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी शामिल होंगे। सीएम योगी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 'चुनावों में हार के नए रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हताशा अब अराजकता की राजनीति में बदल गई है। इनके नेतृत्वकर्ताओं में क्लैरिटी, कैपेसिटी और क्रेडिबिलिटी का पूरा अभाव है। जनादेश का अनादर इसी सोच का परिणाम है।' सीएम योगी ने आगे लिखा, इस अराजकता के विरुद्ध जनजागरण और लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा का संकल्प लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ गोरखपुर में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में सहभागिता करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी नेतृत्व में हम भारत के महान लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का दो दिवसीय संगठनात्मक दौरा करेंगे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 : मथुरा में 5 सीटों का क्या है समीकरण, 2022 में भाजपा ने कितने वोट से मारी थी बाजी?

मथुरा (एजेंसी)



उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ब्रज क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह जिला हमेशा से चुनावी राजनीति के केंद्र में रहा है। मथुरा का चुनावी ताना-बाना मुख्य रूप से जाट, ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिम मतदाताओं के इर्द-गिर्द घूमता है। मथुरा जिले के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें छाता, मांट, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव शामिल हैं।

छाता विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी नारायण चौधरी, मांट से राजेश चौधरी, गोवर्धन से मेघश्याम, मथुरा से श्रीकांत शर्मा और बलदेव से पूरन प्रकाश वर्तमान विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में छाता सीट से लक्ष?मी नारायण चौधरी ने कुल 48,948 वोटों के अंतर से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी तेजपाल सिंह को हराया। लक्ष?मी नारायण को कुल 1,24,414 वोट मिले, जबकि तेजपाल सिंह के खाते में 75,466 वोट पड़े। यहां से पिछली बार कुल 12 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। मांट सीट से वर्तमान विधायक राजेश चौधरी ने 2022 के चुनाव में कुल 9,580 वोटों के अंतर से बसपा प्रत्याशी रहे श्याम सुंदर शर्मा को शिकस्त दी। राजेश चौधरी के खाते में कुल 83,958 वोट आए, जबकि श्याम सुंदर शर्मा को कुल 74,378 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के संजय लाठर कुल 60,585 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में गोवर्धन सीट पर भाजपा के ठाकुर मेघश्याम सिंह ने बसपा प्रत्याशी राज कुमार रावत को 42,507 मतों के अंतर से हराकर यह सीट जीती। मेघश्याम को कुल 1,00,199 वोट हासिल हुए। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के राजकुमार रावत को कुल 57,692 वोट मिले।

लोनी की ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में आग, छह दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

गाजियाबाद (एजेंसी)

गाजियाबाद के लोनी के ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सेक्टर बी-3 स्थित प्लॉट नंबर डी-4 पर संचालित कुमार पैकर्स फैक्ट्री में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी पहली मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही लोनी फायर स्टेशन की तीन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की भयावहता को देखते हुए वैशाली, साहिबाबाद और बागपत के खेकड़ा फायर स्टेशन से भी दमकल गाड़ियां बुलाई गईं। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद छह दमकल गाड़ियों की मदद से सुबह 7:30 बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि इस अग्निकांड में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। फायर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार 4



नवंबर 2026 को सुबह करीब 4:24 बजे लोनी फायर स्टेशन (ट्रॉनिका सिटी) को कुमार पैकर्स फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही लोनी फायर स्टेशन से उपलब्ध तीनों फायर टेंडर फायर सर्विस यूनिट के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल फायर स्टेशन से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर था।

मौके पर पहुंचने पर दमकल कर्मियों ने देखा कि फैक्ट्री के साढ़े तीन मंजिला भवन की पहली मंजिल पर आग पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी वहां पहले से स्थापित अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद फायर सर्विस यूनिट ने मोर्चा संभालते हुए आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों ने आग पर दोनों ओर से पानी डालने के लिए विशेष रणनीति अपनाई। एक ओर हौज पाइप की लाइन सीढ़ियों के रास्ते पहली मंजिल तक पहुंचाई गई, जबकि दूसरी लाइन बगल की फैक्ट्री की छत के रास्ते फैलाकर आग पर पानी की बौछार की गई। इस दौरान आग को भवन की अन्य मंजिलों तक फैलने से रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कमिश्नरेट गाजियाबाद, को भी तत्काल जानकारी दी गई। उनके निर्देश पर वैशाली, साहिबाबाद और बागपत के खेकड़ा फायर स्टेशन से एक-एक अतिरिक्त दमकल गाड़ी घटनास्थल के लिए रवाना की गई।

एक बाइक, पांच दोस्त और मौत का सफर! डिवाइडर से टकराई बाइक, तीन किशोरों की दर्दनाक मौत

नालंदा (एजेंसी)

बिहार के नालंदा जिले में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन किशोरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा हरनौत थाना क्षेत्र में एनएच पर पिलर संख्या 51 के पास हुआ, जहां पांच किशोरों से भरी एक अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सभी पांचों किशोर उछलकर दूर जा गिरे। हादसे में दो सहोदर भाइयों की भी मौत हो गई।

घटना के बाद हरनौत बाजार में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं, मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। अस्पताल में भर्ती घायल अमित कुमार ने बताया कि मंगलवार देर रात सभी दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर बाजार की ओर घूमने निकले थे। बाइक गौतम कुमार चला रहा था। जैसे ही वे एनएच पर पिलर संख्या 51 के पास पहुंचे, अचानक



सड़क पर एक कुत्ता सामने आ गया। कुत्ते को बचाने की कोशिश में बाइक चालक ने संतुलन खो दिया। रफ्तार तेज होने के कारण बाइक सीधे सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार सभी पांचों किशोर उछलकर दूर जा गिरे और अचेत हो गए। मृतक गौतम के भतीजे गुड्डू ने बताया कि रात में सभी लड़के घर के पास पटाखे फोड़ रहे थे। इसके बाद वे अचानक बाइक लेकर घूमने निकल गए। कुछ ही देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही परिजन आनन-फानन में घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को कल्याण बिगहा रेफरल अस्पताल ले गए।

उत्तर प्रदेश सरकार की पहल से परिषदीय विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण का पाठ

लखनऊ (एजेंसी)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने पर भी जोर दे रही है। इसी क्रम में प्रदेश के लगभग 1.32 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों में 1 से 7 नवंबर तक ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में पर्यावरण-अनुकूल आदतें अपनाने और टिकाऊ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है। मिशन लाइफ के सात विषयों पर आधारित इस सप्ताह में प्रदेश के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 1.42 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने और अपने घर-समुदाय तक टिकाऊ जीवनशैली का संदेश पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम में ईको क्लबों की



भूमिका महत्वपूर्ण है। सप्ताह की गतिविधियों की जानकारी और आवश्यक सूचना-शिक्षा-संचार सामग्री निर्धारित पोर्टल से प्राप्त करने की व्यवस्था है। सप्ताह के प्रत्येक दिन एक विषय पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

1 नवंबर को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, 2 नवंबर को ऊर्जा बचाने और 3 नवंबर को जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। वहीं, 4 नवंबर को टिकाऊ खाद्य प्रणालियों पर केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को टिकाऊ जीवनशैली के महत्व से परिचित कराया गया। अब 5 नवंबर को एकल उपयोग प्लास्टिक से दूरी, 6 नवंबर को ई-कचरा कम करने और 7 नवंबर को कचरा कम करने पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के महत्व से परिचित कराया जाएगा। योगी सरकार के नेतृत्व में विद्यालयों को पर्यावरण संरक्षण और जनजागरूकता का केंद्र बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में मिशन लाइफ की शपथ, पोस्टर निर्माण, रचनात्मक गतिविधियां, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों की सहभागिता से ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, प्लास्टिक के विकल्पों, कचरे के पृथक्करण तथा पुनः उपयोग जैसे विषयों पर संदेश प्रसारित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को इन आदतों को विद्यालय तक सीमित न रखकर अपने घर और आसपास भी अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

बिहार : भोजपुर में मां-बेटे की हत्या, बड़े बेटे और बहू से पूछताछ

आरा (एजेंसी)

बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तेंदुनी गांव में मंगलवार देर रात मां और बेटे की हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या धारदार हथियार और हथौड़े से हमला कर की गई। पुलिस को घटनास्थल से खून लगा हथौड़ा मिला है। प्रारंभिक जांच में संपत्ति विवाद की आशंका जताई गई है। इस मामले में मृतक के बड़े बेटे और बहू से पूछताछ की जा रही है। मृतकों की पहचान तेंदुनी गांव के वार्ड नंबर-7 निवासी स्वर्गीय विश्वामित्र सिंह की पत्नी रामवती कुंवर (55) और उनके छोटे बेटे सुनील कुमार (25) के रूप में हुई है।

जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि मंगलवार और बुधवार की रात करीब दो बजे पुलिस को तेंदुनी मोहल्ले में दो लोगों की हत्या की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वह थानाध्यक्ष और पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जांच के दौरान रामवती कुंवर और सुनील कुमार की हत्या की पुष्टि हुई। टनास्थल का निरीक्षण करने के बाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम को बुलाया गया। टीम ने मौके से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा हथौड़ा भी बरामद किया है। प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम के दौरान दोनों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। गर्दन सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की बात सामने आई है। एसडीपीओ ने बताया कि मृतक सुनील कुमार का बड़ा भाई दिनेश कुमार शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम शांति देवी है। प्रारंभिक जांच में परिवार के बीच संपत्ति को लेकर विवाद की बात सामने आई है। पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है कि हत्या की वजह संपत्ति विवाद है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के लिए दिनेश कुमार और उसकी पत्नी शांति देवी को थाने लाया गया है। दोनों से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

मधुबनी फायरिंग केस : एएसआई पर हत्या का केस, गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित, 25 हजार का इनाम घोषित

मधुबनी (एजेंसी)

बिहार के मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड स्थित बलिराजगढ़ में हुई घटना को जिला प्रशासन ने बेहद दुखद और गंभीर बताया है। मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोपी के खिलाफ बाबूबरही थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की पांच विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं।

वहीं, फरार आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा और वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवार और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।



अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी और न ही दोषी के प्रति कोई नरमी दिखाई जाएगी। कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मंगलवार को जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक खोजपुर चौराहा स्थित धरना स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने धरने पर बैठे लोगों और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की। अधिकारियों ने लोगों की बातें सुनीं और घटना को लेकर उनकी भावनाओं तथा चिंताओं को समझा। इस दौरान घटना से बेहद दुखी एक वृद्ध महिला जिलाधिकारी को पकड़कर बिलखने लगीं। जिलाधिकारी ने उन्हें ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक सदर अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित और उनके परिजनों से मुलाकात कर बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ बाबूबरही थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। फरार एएसआई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की पांच विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। प्रशासन ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। पुलिस को आरोपी की तलाश में पूरी तरह सक्रिय बताया गया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि मामले में किसी भी तरह की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। जिला प्रशासन ने मामले में प्रभावी और विधिसम्मत पैरवी सुनिश्चित करने की बात कही है।

टूरिस्ट वीजा पर आए, फिर कहां गए 179 पाकिस्तानी नागरिक? शिक्षा मंत्री ने उठाए सवाल

गोपालगंज (एजेंसी)

बिहार के गोपालगंज जिले में पाकिस्तान से जुड़े एक मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दावा किया है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी से 179 नागरिक टूरिस्ट वीजा पर गोपालगंज आए थे, लेकिन उनके वापस पाकिस्तान लौटने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

मंत्री के इस बयान के बाद विदेशी नागरिकों के आवागमन की निगरानी व्यवस्था और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह दावा गोपालगंज के महेंद्र महिला महाविद्यालय में आयोजित 'विकसित भारत यूथ कॉन्वोकेशन' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1990 के बाद से भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों से जुड़े सभी मामलों की व्यापक और गहन जांच कराई जा रही है। इस जांच के दायरे में पुराने रिकॉर्ड और भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों से संबंधित जानकारियों को शामिल किया गया है। मंत्री के बयान के मुताबिक, पाकिस्तान के रावलपिंडी से 179 नागरिक टूरिस्ट वीजा पर गोपालगंज आए थे। हालांकि, उनके वापस अपने देश लौटने का कोई आधिकारिक प्रमाण सरकार के पास नहीं है। इस जानकारी के सामने आने के बाद यह पता लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है कि ये नागरिक किस उद्देश्य से गोपालगंज आए थे और उनके लौटने से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध क्यों नहीं हैं। वर्ष 1990 के बाद भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों से जुड़े मामलों की जांच का दायरा व्यापक रखा गया है।

हरदोई से गिरफ्तार हुआ 'काली सरकार', आर्मी की तरह ड्रेस पहनकर लगाता था 'दिव्य दरबार'

हरदोई (एजेंसी)

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर क्षेत्र में 'दिव्य दरबार' लगाकर चर्चा में आए काली सरकार उर्फ प्रदीप शुक्ला को हरदोई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ वर्ष 1993 और 1998 में दर्ज आपराधिक मामलों में न्यायालय से जारी समन के बावजूद वह पेश नहीं हो रहा था। अदालत में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। हरदोई के चौहान थोक निवासी प्रदीप शुक्ला झांसी के कुरैंचा गांव स्थित मंदिर में सत्यानंद शुक्ला उर्फ काली सरकार के नाम से रह रहा था। वह आर्मी जैसी ड्रेस पहनकर दरबार लगाता था और लोगों की बीमारियां ठीक करने का दावा करता था। सोशल मीडिया पर उसके एक



लाख से अधिक फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। हरदोई पुलिस ने इससे पहले 10 अक्टूबर को भी उसे हिरासत में लिया था, लेकिन पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे न्यायालय से राहत मिल गई थी।

रिकॉर्ड दुरुस्त होने के बाद पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एक नाबालिग से कथित यौन उत्पीड़न का मामला भी दर्ज होने की जानकारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ नगर हरदोई अजीत चौहान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को थाना कोतवाली शहर के हिस्ट्रीशीटर प्रदीप शुक्ला पुत्र मायारा, निवासी चौहान थोक, के खिलाफ कोर्ट से वारंट प्राप्त किया गया। इसके बाद प्रदीप शुक्ला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, प्रदीप शुक्ला के खिलाफ पहला मामला साल 1993 में दर्ज हुआ था। यह मुकदमा आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत दर्ज किया गया था। इसी साल उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आईपीसी की धारा 394, 397 और 411 लगाई गई। इसके अलावा, साल 1998 में आईपीसी की धारा 324 के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। इन पुराने मामलों में आरोपी लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहा था।

धीरेंद्र शास्त्री पर अखिलेश का हमला, कहा- UP-MP सीमा पर लगना चाहिए ईशनिंदा करने वालों के प्रवेश वर्जित का बोर्ड'

लखनऊ (एजेंसी)

प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री की भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद गहराता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए धीरेंद्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदुवंशियों और रघुवंशियों, दोनों की भावनाएं आहत की गई हैं। अब ऐसे लोगों को न ब्रज में प्रवेश मिलेगा और न अवध में।

अखिलेश ने यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर नाकाबंदी का बोर्ड लगा देना चाहिए, जिस पर लिखा हो कि 'ईशनिंदा' करने वालों का उत्तर प्रदेश की धर्मभूमि पर प्रवेश वर्जित है। सपा मुखिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म



'एक्स' पर लिखा है, 'इन्होंने यदुवंशियों और रघुवंशियों दोनों की भावनाएं आहत की हैं। अब इन्हें न ब्रज में प्रवेश मिलेगा, न अवध में। अब न तो कोई सच्चा रघुवंशी इनका स्वागत करेगा, न सच्चा यदुवंशी। उप्र-मप्र के बार्डर पर इनकी नाकाबंदी का बोर्ड लग जाना चाहिए, जिस पर लिखा हो, 'ईशनिंदा' करनेवालों का उप्र की धर्म-भूमि पर प्रवेश वर्जित है।'

सपा मुखिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा है, 'इन्होंने यदुवंशियों और रघुवंशियों दोनों की भावनाएं आहत की हैं। अब इन्हें न ब्रज में प्रवेश मिलेगा, न अवध में। अब न तो कोई सच्चा रघुवंशी इनका स्वागत करेगा, न सच्चा यदुवंशी

अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा, जिसने धर्म-मजहब नहीं छोड़ा, वो अगली बार सम्प्रदायों पर छींटाकशी करने से बाज नहीं आएगा।

समझाने की जरूरत नहीं, अगला नंबर किस का है। नेपाल बार्डर भी बंद करना पड़ेगा नहीं तो उधर से इधर आना अधिक पास पड़ेगा। सपा अध्यक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक और धार्मिक टकराव से जोड़ते हुए आगे लिखा, लगता है उत्तर प्रदेश में किसी बाहरी के इशारे पर किसी की राजनीतिक-धार्मिक सत्ता को चुनौती देने का काम हो रहा है। आपस की टकराहट में सियासी लोग भगवान को क्यों ला रहे हैं। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के में आयोजित श्रीराम कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान राम और श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि 'उनके राम सीधे हैं, जबकि कृष्ण टेढ़े' हैं। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के नाम, स्वरूप और चाल-ढाल को भी इसी संदर्भ में टेढ़ा बताते हुए भगवान राम को हर लिहाज से सीधा बताया था। धीरेंद्र शास्त्री के इस कथन के सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया और धार्मिक व राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं।

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव परिणाम : तीन भारतीय-अमेरिकी जीते, ओहियो में रामास्वामी पिछड़े

वाशिंगटन (एजेंसी)



पिया दांडिया ने रिपब्लिकन केसी असकर को हराकर फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट (संसदीय क्षेत्र) से जीत हासिल की है। इस जीत से डेमोक्रेट्स को दक्षिण फ्लोरिडा में एक नया सीमा-निर्धारित चुनावी क्षेत्र मिल गया है और अमेरिकी कांग्रेस में एक और भारतीय-अमेरिकी महिला शामिल हो गई हैं, दांडिया पूर्व स्कूल प्रिंसिपल और व्हाइट हाउस फेलो रह चुकी हैं।

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजे आने लगे हैं। फिलहाल तीन भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेट्स के चुनाव जीतने या फिर से चुने जाने के आसार हैं, जबकि ओहियो में गवर्नर पद की कड़े मुकाबले में रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी, डेमोक्रेट एमी एक्टन से पीछे चल रहे हैं। सीबीएस न्यूज के अनुसार, पिया दांडिया ने रिपब्लिकन केसी असकर को हराकर फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट (संसदीय क्षेत्र) से जीत हासिल की है।

इस जीत से डेमोक्रेट्स को दक्षिण फ्लोरिडा में एक नया सीमा-निर्धारित चुनावी क्षेत्र मिल गया है और अमेरिकी कांग्रेस में एक और भारतीय-अमेरिकी महिला शामिल हो गई हैं। दांडिया पूर्व स्कूल प्रिंसिपल और व्हाइट हाउस फेलो रह चुकी हैं। इनके माता-पिता भारत से आकर अमेरिका में बस गए थे, उन्होंने शिक्षा, किफायती जीवन-यापन और आर्थिक अवसरों के मुद्दों पर अपना चुनाव प्रचार किया था। वर्जीनिया में, डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन सुहास सुब्रमण्यम ने राज्य के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से फिर से जीत हासिल की है। उन्होंने रिपब्लिकन डेव बेकविथ और निर्दलीय उम्मीदवार अहसेन मलिक को हराया। एनबीसी न्यूज़ ने शाम को ही उनकी जीत का अनुमान जता दिया था। सुब्रमण्यम, जो 2024 में वर्जीनिया से अमेरिकी कांग्रेस के पहले भारतीय-अमेरिकी सदस्य बने थे, ने कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल में उनका ध्यान संघीय कर्मचारियों की सुरक्षा, जीवन-यापन की लागत कम करने, स्वास्थ्य सेवा में की गई कटौती को ठीक करने, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तथा डेटा सेंटरों के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने पर होगा।

उनके चुनाव अभियान की ओर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन असली काम तो अब शुरू हो रहा है। मैं वाशिंगटन में बदलाव लाने के लिए अपने समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। पड़ोसी राज्य मैरीलैंड में, डेमोक्रेटिक गवर्नर वेस मूर ने रिपब्लिकन डैन कॉक्स को हराया, जिससे भारतीय-अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर का कार्यकाल भी बरकरार रहा। मतदान खत्म होने के कुछ ही समय बाद सीबीएस न्यूज ने मूर की दोबारा जीत का अनुमान जता दिया था। वहीं ओहियो में एक्टन ने रामास्वामी पर अपनी बढ़त बनाए रखी, हालांकि मतगणना आगे बढ़ने के साथ ही उनकी बढ़त कम होती गई। चुनाव-रात की एक रिपोर्ट में एनबीसी न्यूज के नतीजों का हवाला दिया गया था, जिसके अनुसार रात 9 बजे तक लगभग 46 प्रतिशत वोटों की गिनती हो चुकी थी। इसमें एक्टन को 54.3 प्रतिशत और रामास्वामी को 42.8 प्रतिशत वोट मिले थे। उस समय तक नतीजे घोषित नहीं किए गए थे।

बायोटेक्नोलॉजी उद्यमी और पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामास्वामी, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त है, अब रिपब्लिकन गवर्नर माइक डीवाइन की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं (क्योंकि डीवाइन का कार्यकाल पूरा हो रहा है)। एक और अहम घटनाक्रम में, सीबीएस न्यूज के रात 9:29 बजे तक के अनुमान अनुसार, डेमोक्रेट कीशा लांस बॉटम्स ने जॉर्जिया में गवर्नर का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने रिपब्लिकन रिक जैक्सन को हराया। अटलांटा की पूर्व मेयर अमेरिकी इतिहास में गवर्नर चुनी जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनने जा रही हैं। उनकी जीत ने जॉर्जिया के गवर्नर पद पर रिपब्लिकन पार्टी के दो दशकों से अधिक के नियंत्रण को खत्म कर दिया है। 'पोलिटिको' के चुनाव-रात अलर्ट के अनुसार, फ्लोरिडा में गवर्नर पद के चुनाव में रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य बायरन डोनाल्ड्स ने डेमोक्रेट डेविड जॉली को हराया।

डोनाल्ड्स, रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डेसेंटिस की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवारों ने भी राज्य विधायी चुनावों में शुरुआती दौर में अच्छी बढ़त बनाई है। जॉर्जिया में, हाउस डिस्ट्रिक्ट 97 से डेमोक्रेट ज्योत सिंह, रिपब्लिकन यासीन मोघाजी से आगे चल रहे हैं। अनौपचारिक नतीजों के अनुसार, सिंह को 10,176 वोट मिले हैं, जबकि मोघाजी को 4,226 वोट मिले हैं; वोटों की गिनती अभी जारी है।

ओहियो से हारे विवेक रामास्वामी, एमी ने 20 साल बाद डेमोक्रेटिक पार्टी को दिलाई जीत

वाशिंगटन (एजेंसी)



भारतीय मूल के रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी ने ओहियो के गवर्नर चुनाव में डेमोक्रेट एमी एक्टन के सामने हार स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही उनका वह हाई-प्रोफाइल चुनाव अभियान समाप्त हो गया, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस का जोरदार समर्थन प्राप्त था। यह हार रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बड़ा चुनावी झटका है, खासकर उस राज्य के लिए जहां 2024 में ट्रंप ने आसानी से जीत हासिल की थी।

60 वर्षीय डॉक्टर और ओहियो की पूर्व स्वास्थ्य निदेशक, एक्टन मंगलवार रात (स्थानीय समयानुसार), ओहियो की पहली महिला गवर्नर चुनी गईं। वह 2006 के बाद से इस पद पर जीतने वाली पहली डेमोक्रेट बन गई हैं। चुनाव की रात आए नतीजों के अनुसार, एक्टन को लगभग 51 प्रतिशत वोट मिले, जबकि रामास्वामी को 46 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। वहीं, लिबर्टेरियन उम्मीदवार डॉन किसिक को लगभग तीन प्रतिशत वोट मिले। यह परिणाम डेमोक्रेट्स की ओर लगभग 16 प्रतिशत अंकों के झुकाव को दर्शाता है। इसकी तुलना में, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने ओहियो में 11 प्रतिशत अंकों के अंतर से जीत हासिल की थी। ओहियो में चुनाव की रात अपने समर्थकों के बीच रामास्वामी ने अपनी हार स्वीकार की और बताया कि उन्होंने एक्टन को बधाई देने के लिए उनसे संपर्क किया है। अपने संबोधन में, रामास्वामी ने समर्थकों का धन्यवाद किया और कहा कि वह सार्वजनिक जीवन से बाहर रहकर भी ओहियो की सेवा करना जारी रखेंगे।

उन्होंने अपने माता-पिता, पत्नी अपूर्वा, अपने तीन बच्चों और अपने साथी उम्मीदवार (रनिंग मेट), ओहियो सीनेट के अध्यक्ष रॉब मैकोली का भी आभार व्यक्त किया। 41 वर्षीय रामास्वामी, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के अपने असफल अभियान के दौरान एक प्रमुख राष्ट्रीय रिपब्लिकन चेहरे के रूप में उभरे थे।

अमेरिका की जनता का संदेश साफ, उन्हें नहीं चाहिए ऐसा नेता जो लोगों को बांटे : ओबामा

वाशिंगटन (एजेंसी)



अमेरिकी मध्यावधि चुनाव 2026 में रिपब्लिकन पार्टी को जोर का झटका लगा है। कई अहम सीटों पर वो हार गई है। नतीजे सामने आने के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि ये जनता लोगों को बांटने की कोशिश करने वाली सियासत को नकार रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ओबामा ने कहा, अमेरिकी जनता ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है।

वो ये कि वो ऐसी राजनीति चाहते हैं जो लोगों को बांटने के बजाय उन्हें एकजुट करे, और ऐसे नेता चाहते हैं जो उनके सामने आने वाली चुनौतियों का ठोस समाधान प्रस्तुत कर सके। उन्होंने जीत का कारण साझा मूल्यों और एकजुटता से आगे बढ़ने की सोच को माना। आगे लिखा, ये नतीजे इसलिए संभव हो पाए क्योंकि देश के हर हिस्से से बेहतरीन उम्मीदवार आगे आए। यहां तक कि उन इलाकों से भी, जहां जीत की उम्मीद बहुत कम मानी जाती थी। वे अलग-अलग पृष्ठभूमि से आए थे और उनके राजनीतिक विचार भी अलग-अलग थे, लेकिन वे कुछ साझा मूल्यों, जनसेवा में विश्वास और अपने जिलों व राज्यों के लोगों को सबसे ऊपर रखने की प्रतिबद्धता से एकजुट थे। ओबामा ने मध्यावधि चुनाव प्रचार में जुटे रहे कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स का भी आभार जताया। उन्होंने कहा, हम उन हजारों चुनाव कार्यकर्ताओं और दोनों पार्टियों के स्वयंसेवकों के भी आभारी हैं, जिन्होंने चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने में मदद की और हमारे लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक को बखूबी निभाया।

पूर्व राष्ट्रपति ने अपने बयान में लोगों को भविष्य के लिए तैयार रहने की बात कही। उन्होंने कहा, 'मौजूदा प्रशासन का कार्यकाल अभी दो साल और है। ऐसे में हमारा काम और अहम हो जाता है। अब पार्टी और सहयोगियों को अपनी आस्तीनें चढ़ाकर काम करना होगा। जहां भी हमारे पास बदलाव लाने का अधिकार है, वहां बदलाव लाना होगा ताकि आगे और नुकसान न होने दें और भविष्य के लिए तैयार हों।

अमेरिका से बातचीत शांति का विकल्प, लेकिन राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा उत्तर कोरिया : किम यो जोंग

सोल (एजेंसी)



उत्तर कोरिया ने बुधवार को कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत शांति स्थापित करने का एक विकल्प है, लेकिन इसे अपने राष्ट्रीय हितों के लिए वो जरूरी नहीं मानता। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने यह बयान देते हुए अमेरिका पर प्योंगयांग के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति जारी रखने का आरोप लगाया।

उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के हवाले से योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि किम यो जोंग ने कहा कि अमेरिका लगातार ऐसे संकेत दे रहा है, जिनसे उत्तर कोरिया को उसके वास्तविक इरादों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'शांति के विकल्पों में निश्चित रूप से बातचीत भी शामिल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बातचीत हमारे राष्ट्रीय हितों के बराबर है।' उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस से 6 अरब डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी चोरी के मामले में उत्तर कोरिया की संलिप्तता का आरोप लगाया है। उत्तर कोरिया ने इस आरोप को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक उकसावे की कार्रवाई बताया है। किम यो जोंग ने बुधवार को एक बार फिर इस आरोप को अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीति का उदाहरण बताया।

उन्होंने कहा कि तथाकथित उत्तर कोरियाई क्रिप्टोकरेंसी हैकिंग का मामला अमेरिका की प्योंगयांग विरोधी नीति की वास्तविक प्रकृति की केवल एक झलक है। उन्होंने दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के विदेश मंत्रियों की हालिया त्रिपक्षीय बैठक का भी उल्लेख किया। इस बैठक में तीनों देशों ने उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। किम ने इन देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यासों को भी उत्तर कोरिया के खिलाफ शत्रुतापूर्ण गतिविधियों का हिस्सा बताया। किम यो जोंग ने कहा कि अमेरिका को उत्तर कोरिया के प्रति अपनी शत्रुतापूर्ण नीति छोड़नी होगी। उनके मुताबिक, सभी समस्याओं के समाधान के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक वाशिंगटन अपनी टकराव की नीति नहीं बदलता, तब तक प्योंगयांग के पास अमेरिका के साथ बातचीत की मेज पर बैठने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा, उत्तर कोरिया को ऐसे अविश्वसनीय और शत्रुतापूर्ण लोगों के साथ आमने-सामने बैठने की जरूरत नहीं है, जो अपनी टकराव की नीति छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

जम्मू-कश्मीर : श्रीनगर में आग से 80 अस्थायी शेल्टर जलकर खाक, दो की मौत

श्रीनगर (एजेंसी)

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आग लगने की वजह से कम से कम दो कबाड़ इकट्ठा करने वालों की मौत हो गई और करीब 80 अस्थायी शेल्टर जलकर खाक हो गए। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के बेमिना के दुर्बल में सुबह-सुबह अस्थायी शेल्टर में लगी भीषण आग में दो कबाड़ इकट्ठा करने वालों की मौत हो गई। उन्होंने कहा, आग रात करीब 12:23 बजे लगी, जिसने तिरपाल और लकड़ी से बने करीब 80 अस्थायी शेल्टरों को अपनी चपेट में ले लिया।

आग में एक खाली पोल्ट्री फार्म और एक टिपर को भी नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने बताया, फायर स्टेशन जेवीसी और रावलपोरा से फायर टेंडर, साथ ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर बटमालू से अतिरिक्त मदद के लिए बुलाए गए, ताकि आग पर काबू पाया जा सके। चश्मदीदों ने बताया कि आग बुझाने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाने से पहले ही आग पूरे इलाके में फैल चुकी थी। आग पर काबू पाने के बाद मलबे से दो लाशें मिलीं। मरने वाले दोनों लोग दिल्ली के रहने वाले थे। उनकी पहचान मोहम्मद नूर आलम (27) और अल अमीन (16) के तौर पर हुई। दोनों बेमिना के दुर्बल में स्क्रैप इकट्ठा करने का काम करते थे। अधिकारियों ने कहा, एफएसएल की कार्रवाई पूरी होने के बाद दोनों शव स्थानीय पुलिस को सौंप दिए गए। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चला है। पुलिस ने इस घटना में केस दर्ज कर लिया है। इन दिनों घाटी में सूखे मौसम की वजह से आग लगने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। अधिकारियों ने कहा है कि लगभग 80 से 95 प्रतिशत आग लगने की वजह इंसानी गतिविधियां होती हैं। बिना देखरेख के या ठीक से न बुझाए गए कैंपफायर आग लगने का एक मुख्य कारण हैं।

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शिवसेना-BT का केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर हमला, मांगा अमित शाह का इस्तीफा

मुंबई (एजेंसी)



शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। लॉरेन्स बिश्नोई गैंग के नाम से व्यापारियों, बिल्डर्स, सिने अभिनेताओं और निर्माताओं को धमकियां मिल रही हैं। ऐसे महानायक को बुलेटप्रूफ पिंजरे में घूमना पड़ रहा है।

बच्चन और उनके परिजनों को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। यह मुख्यमंत्री फडणवीस और केंद्रीय गृहमंत्री शाह की असफलता है। अभिनेता अमिताभ बच्चन के 'बुलेटप्रूफ ग्लास' के अंदर से अपने प्रशंसकों का अभिवादन करने की एक तस्वीर के साथ शिवसेना-यूबीटी ने अपने मुखपत्र 'सामना' में 'पिंजरे में बच्चन!' शीर्षक के साथ एक लेख लिखा है। शिवसेना-यूबीटी ने कहा कि यह मौजूदा प्रशासन के तहत कानून-व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने का सबूत है। मुखपत्र 'सामना' में छपे संपादकीय में ठाकरे गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। संपादकीय में कहा गया है कि देश में सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक स्तर तक गिर गई है। शिवसेना-यूबीटी ने कहा, शाह ने मानो अपने स्वार्थ के लिए एक अदृश्य शक्ति का निर्माण किया है और उस अदृश्य शक्ति के जरिए देश में किसी को भी धमकियां दिलाई जाती हैं, किसी से भी वसूली की जाती है या गोलीबारी करके लाशें गिराई जाती हैं।

इसी के लिए अमिताभ बच्चन (आयु 84 वर्ष) जैसे महानायक को बुलेटप्रूफ कांच का पिंजरा लेकर घूमना पड़ रहा है। अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी के पास हुई गोलीबारी की हालिया घटनाओं और नागपुर में सर्राफा व्यापारियों से रंगदारी मांगने के मामलों का जिक्र करते हुए शिवसेना-यूबीटी ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों हाई-प्रोफाइल फिल्मी हस्तियां, बड़े कारोबारी और आम नागरिक लगातार डर के साये में जी रहे हैं? उद्धव ठाकरे गुट ने सवाल किया कि अपराधी गिरोह, खासकर लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क, बिना किसी डर के कैसे काम कर रहे हैं? आरोप लगाया गया है कि गृह मंत्रालय के एक आदेश ने राज्य पुलिस को गुजरात की साबरमती जेल से बिश्नोई को हिरासत में लेने से रोक दिया है, जिससे जेल में बंद इस गैंगस्टर को एक तरह का 'अदृश्य सुरक्षा कवच' मिल गया है।

संपादकीय में पूछा गया, एक तरफ सत्ताधारी नेता भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक, बिल्डर और फिल्मी हस्तियां लगातार खौफ में जी रही हैं।

झारखंड में नहीं थम रहा 'गजराजों' की मौत का सिलसिला, पश्चिमी सिंहभूम में फिर मिला हाथी का शव

रांची (एजेंसी)

झारखंड में हाथियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला पश्चिमी सिंहभूम के टंकुरा का है। यहां बुधवार सुबह एक खेत में हाथी का शव मिला। पिछले दो महीनों में राज्य के अलग-अलग वन क्षेत्रों में हाथियों की मौत की चार घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ाजामदा ओपी क्षेत्र के टंकुरा बस्ती स्थित बुरमा टोली के पास बुधवार सुबह ग्रामीणों ने खेत में एक हाथी का शव देखा। इससे पहले मंगलवार शाम करीब 20 हाथियों का झुंड गांव की सीमा में पहुंच गया था।

ग्रामीणों के मुताबिक, उन्होंने वन विभाग को सूचना दी और मदद मांगी। लेकिन कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाला। वे पूरी रात जागकर हाथियों के झुंड को गांव से दूर भगाने में जुटे रहे। सुबह उन्हें खेत में एक हाथी मृत मिला। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। ग्रामीणों ने करंट लगने की आशंका जताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक कारण सामने आएगा। ग्रामीणों ने वन विभाग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इससे पहले 28 अक्टूबर को लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बिशुनपुर जंगल में एक हाथी मृत मिला था। बुधवार शाम शव मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अगले दिन रेंजर नंदकुमार महतो के नेतृत्व में अधिकारियों और पशु चिकित्सकों की टीम ने जांच की। रेंजर ने हाथियों के आपसी संघर्ष में मौत की आशंका जताई। अक्टूबर की शुरुआत में पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर क्षेत्र के भांगांव में भी एक मादा हाथी मृत मिली थी। ग्रामीणों ने देखा कि उसके दोनों दांत गायब थे। इससे हाथी दांत की तस्करी के लिए शिकार किए जाने की आशंका जताई गई।

राहुल गांधी की 'इंसाफ रैली' पर बरसे भाजपा नेता, कहा-1984 का इंसाफ लेकर आते

चंडीगढ़ (एजेंसी)



पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बुधवार को संगरूर जिले में होने वाली 'इंसाफ रैली' को लेकर भाजपा नेता सतीश पूनिया ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 1984 में जो कुछ हुआ था, उसे देश की जनता आज तक नहीं भूली है। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी को पंजाब में इंसाफ की बात करने से पहले 1984 के मामले पर जवाब देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अच्छी बात तो यह होती कि राहुल गांधी इस मामले में पंजाब की जनता के सामने जवाब लेकर आते। पूनिया ने कहा कि 1984 की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को लेकर आज भी सवाल उठते हैं। ऐसे में राहुल गांधी जब पंजाब आकर राज्य के हक की बात करते हैं, तो उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी को बहस की चुनौती दिए जाने पर सतीश पूनिया ने कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को करीब 55 साल तक शासन करने का अवसर दिया है। ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन पर आम नागरिक भी कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, लेकिन पार्टी के पास उनके जवाब नहीं होते।

राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से बहस करने से पहले अपनी ही पार्टी के भीतर देखना चाहिए और यह परखना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारों ने क्या काम किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी आम भाजपा कार्यकर्ता के साथ भी बहस कर लें, तो उन्हें कांग्रेस से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसी बीच, 1984 का जिक्र करते हुए पूनिया ने कहा कि अगर इतिहास को देखें तो 1984 के जख्मों की पृष्ठभूमि में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन उस समय के दंश को देश कभी भूल नहीं सकेगा। कांग्रेस के कुछ नेता जेल गए और कुछ मामलों में आज भी मुकदमे चल रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि पंजाब कभी सुख-शांति और भाईचारे के लिए जाना जाता था, लेकिन 1984 की घटनाओं ने राज्य और देश के सामने गहरा जख्म छोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि उन घटनाओं से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए दिल्ली और हरियाणा की भाजपा सरकारों ने प्रयास किए हैं। सतीश पूनिया ने कांग्रेस की ओर से 1 नवंबर को आयोजित रैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस दिन 1984 में नरसंहार और कत्लेआम हुआ था, उसी दिन बड़ी रैली आयोजित करने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या थी, यह समझ से परे है।

उज्जैन : भस्म आरती में महाकाल का शृंगार देख भक्त रह गए दंग, भांग से टीका बनाकर फूलों से सजाया फिर चढ़ाई भस्म

उज्जैन (एजेंसी)



विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में कार्तिक कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि बुधवार की सुबह 4 बजे हुई भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन-अभिषेक कर आकर्षक शृंगार किया गया। शृंगार के बाद बाबा महाकाल को भस्म रमाई गई। इस दौरान भक्तों ने इन दिव्य दर्शनों का लाभ लिया और जय श्री महाकाल के उद्घोष से मंदिर परिसर गूंज उठा। मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि बुधवार पर आज श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का विशेष शृंगार किया गया।

इस दौरान भस्म आरती के लिए सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही पण्डे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर फलों के रस से बने पंचामृत को अर्पित कर किया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंड माला धारण करवाई गई। बुधवार के शृंगार की विशेष बात यह रही कि आज बाबा महाकाल का भांग से शृंगार कर चन्द्रमा और बेलपत्र अर्पित किए गए। बाबा महाकाल की भस्म आरती में बड़ी संख्या मे श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने बाबा महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और बाबा महाकाल की भक्ति में लीन होकर जय श्री महाकाल का उद्घोष करने लगे। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार स्वरूप में दर्शन देते हैं।

कोरबा में सड़क हादसा, स्कूटी और बाइक टक्कर के बाद दो लोगों की मौत

कोरबा (एजेंसी)



छत्तीसगढ़ के कोरबा में बुधवार सुबह सड़क हादसा हो गया। कुसमुंडा के गेवरा-टीपर मार्ग पर स्कूटी और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन सवार ट्रेलर की चपेट में आ गए। हादसे में बाइक सवार युवक ट्रेलर के पहियों के नीचे आ गया, जबकि स्कूटी सवार युवती की भी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। बताया जा रहा है कि रेलवे अंडरब्रिज मरम्मत के लिए बंद होने से भारी वाहनों का दबाव टीपर मार्ग पर बढ़ गया था। इसी वजह से इस वैकल्पिक मार्ग पर यातायात काफी ज्यादा था। हादसे के बाद वैकल्पिक मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही कुसमुंडा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस पहचान की कोशिश कर रही है।

बता दें कि इससे पहले रविवार देर रात भी एक भीषण सड़क हादसा हो गया था। उत्तर प्रदेश के हाटा कोतवाली क्षेत्र के थारुडीह गांव के पास एक वैन के ट्रेलर से टकराने से छह लोगों की मौत हो गई थी और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। मृतकों में से पांच लोग एक ही परिवार के थे, जो एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया था कि रविवार रात को आठ लोग एक ओमनी वैन में सवार होकर तिलक समारोह में शामिल होने के बाद हाटा से कसानगंज स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान हाटा इलाके में वैन अहीराउली की तरफ से हाटा आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। वैन में सवार आठ लोगों में से छह की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि दो घायलों को पुलिस ने तुरंत इलाज के लिए गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। उन्होंने कहा था कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। परिवारों को इस घटना की सूचना दे दी गई है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है और आगे की जांच चल रही है। मृतकों के एक रिश्तेदार ने बताया था कि 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 घायलों को इलाज के लिए गोरखपुर भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद हमें शव सौंप दिए जाएंगे।

महिला और पुरुष टीम के सपोर्ट स्टाफ में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू, बीसीसीआई ने जारी किया नोटिस

मुंबई (एजेंसी)



भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सीनियर महिला क्रिकेट टीम के लिए फील्डिंग कोच और सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के लिए हेड फिजियोथेरेपिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये दोनों पद राष्ट्रीय टीमों के साथ काम करने और खिलाड़ियों के विकास, उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने तथा अपने-अपने क्षेत्रों में उच्च मानक बनाए रखने में योगदान देने का अवसर प्रदान करते हैं। ये दोनों पद क्रमशः मुनीश बाली और कमलेश जैन की जगह भरने के लिए निकाले गए हैं।

फील्डिंग कोच सीनियर महिला टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में फील्डिंग प्रदर्शन को विकसित करने और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इस भूमिका में फील्डिंग के व्यापक कार्यक्रम तैयार करना, प्रैक्टिस और मैच के दिन सत्र आयोजित करना और खिलाड़ियों के कौशल को बेहतर बनाने के लिए उन्हें व्यक्तिगत कोचिंग देना शामिल होगा। चयनित फील्डिंग कोच को तकनीक की मदद से खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करना होगा। उन्हें खिलाड़ियों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, उनके लिए प्रदर्शन लक्ष्य तय करना और यह देखना होगा कि वे तय मानकों पर कितना खरे उतर रहे हैं।

उनकी जिम्मेदारी यह भी होगी कि टीम की फील्डिंग का स्तर हमेशा ऊंचा बना रहे, चाहे खिलाड़ी चोट के कारण उपलब्ध न हों, अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में व्यस्त हों या टीम किसी भी फॉर्मेट और अलग-अलग परिस्थितियों में खेल रही हो। फील्डिंग कोच के पद के लिए आवेदन करने वालों को निर्धारित पात्रता मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना होगाः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत या किसी अन्य देश का प्रतिनिधित्व किया हो; कम से कम बीसीसीआई लेवल 'बी' कोचिंग सर्टिफिकेशन (या किसी प्रतिष्ठित संस्था से इसके समकक्ष योग्यता) हो और साथ ही कम से कम 30 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हों; या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय टीम को कम से कम एक सीजन के लिए, अथवा किसी टी20 फ्रेंचाइजी या राज्य स्तरीय टीम को कम से कम दो सीजन के लिए कोचिंग दी हो। उम्मीदवारों को खेल की गहरी समझ होनी चाहिए, उच्चतम स्तर पर काम करने का अनुभव होना चाहिए, और विभिन्न संस्कृतियों वाले लोगों की टीम में काम करने की क्षमता होनी चाहिए।

इसके साथ ही, उनमें बेहतरीन कम्युनिकेशन, टीम वर्क और लोगों को प्रबंधित करने के कौशल होने चाहिए। सीनियर पुरुष टीम के हेड फिजियोथेरेपिस्ट चोटों के प्रबंधन, उनकी रोकथाम और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। वे बीसीसीआई की स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन टीम, स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन के प्रमुख, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कोचिंग स्टाफ और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर काम करेंगे। इस भूमिका में मैच के दिन फिजियोथेरेपी और रोजमर्रा की चोटों में सहायता देना, चोटों का निदान करना और साक्ष्य-आधारित उपचार, पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) तथा खेल में वापसी की योजनाएं तैयार करना शामिल होगा। फिजियोथेरेपिस्ट मस्कुलोस्केलेटल (मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी) स्क्रीनिंग करेंगे, चोट लगने के जोखिमों का आकलन करेंगे, खिलाड़ियों के वर्कलोड की निगरानी करेंगे और क्लिनिकल रिकॉर्ड तथा उपलब्धता रिपोर्ट बनाए रखेंगे।

इस पद में चिकित्सा पेशेवरों और राज्य टीम के फिजियोथेरेपिस्टों के साथ समन्वय करना भी शामिल है, ताकि देखभाल की निरंतरता बनी रहे। इसके अलावा, इसमें शोध, पेशेवर शिक्षा और क्लिनिकल प्रोटोकॉल में सुधार लाने में योगदान देना भी शामिल होगा। दोनों पदों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2026 को शाम 5:00 बजे है।

बर्थडे स्पेशल : विराट कोहली के 38वें जन्मदिन पर उनके शरीर पर बने 13 'टैटू'

नई दिल्ली (एजेंसी)



भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली गुरुवार को 38 साल के हो जाएंगे। क्रिकेट विराट के जीवन का पहला प्यार है। इस खेल में खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ कड़ी मेहनत की है और ये सिलसिला अब भी जारी है। क्रिकेट के अलावा विराट को टैटू बेहद पसंद है। विराट कोहली टैटू के बहुत बड़े फैन हैं। इसका सबूत उनके शरीर पर बने टैटू की संख्या देती है। विराट ने अपने पूरे शरीर के अलग-अलग हिस्सों में 13 टैटू बनाए हैं जिनका अलग-अलग अर्थ है।

1.विराट ने अपने बाएं ट्राइसेप 'ओम का निशान' बनवाया है। ये टैटू आध्यात्मिकता और उस यूनिवर्सल आवाज को दिखाता है जो ब्रह्मांड में हमेशा एक जैसी रहती है।

2.कोहली ने अपने बाएं कंधे पर एक मॉनेस्ट्री की तस्वीर बनवाई है। मठ एक इमारत या इमारतों का ग्रुप होता है जहां एक धार्मिक समुदाय, ज्यादातर साधु समाज से दूर रहते हुए साधना करते हैं।

3.पूर्व कप्तान की राशि स्कॉर्पियो है। इस वजह से दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से में उन्होंने स्कॉर्पियो का निशान बनवाया है। स्कॉर्पियो राशि वाले बहुत ज्यादा पैशन, इंटेंसिटी और समर्पण दिखाने के लिए जाने जाते हैं। कोहली में ये सारी खूबियां दिखती हैं।

4.कोहली ने अपने बाएं हाथ पर 269 का टैटू बनवाया है। यह उनका टेस्ट कैप नंबर है।

5.विराट का वनडे कैप नंबर 175 है। उन्होंने अपने बाएं हाथ पर इस नंबर का भी टैटू बनवाया है।

6.'किंग' के नाम से मशहूर कोहली ने अपने बाएं हाथ पर पिता प्रेम कोहली और माता सरोज कोहली के नाम का टैटू बनवाया है।

7.कोहली के बाएं ऊपरी हाथ पर एक खास जापानी समुराई टैटू है, जो पारंपरिक बुशिडो कोड ऑफ डिसिप्लिन और ऑनर से प्रेरित है। विराट खुद ताकत, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की मिसाल हैं, ये गुण समुराई टैटू डिजाइन से जुड़े हैं।

8.विराट के बाएं कंधे पर जापानी समुराई टैटू के ठीक ऊपर एक दिव्य आंख का टैटू भी है। 'गॉड्स आई' टैटू उनके इस विश्वास को दिखाता है कि उनके हर काम पर नजर रखी जा रही है। इससे वह अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार रहते हैं।

9.पियोनी टैटू विराट कोहली के बाएं कंधे पर बने आर्टवर्क का हिस्सा है। इस फूल का एशिया में, खासकर चीनी परंपरा में, बहुत गहरा सांस्कृतिक महत्व है, जहां इसे अक्सर धन, खुशहाली, सम्मान और ऊंचे सामाजिक स्तर से जोड़ा जाता है।

10.विराट के दाएं फोरआर्म पर मेटाट्रॉन क्यूब, एक क्यूबिक पैटर्न और आध्यात्मिक सिंबल का एक रूप है।

11.कोहली के बाएं हाथ पर कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हुए भगवान शिव की एक तस्वीर है। उसके बैकग्राउंड में मानसरोवर झील है। टैटू विराट के आध्यात्मिक जुड़ाव को दिखाता है।

12.आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले कोहली ने अपने बाएं हाथ पर पूरी आस्तीन का 'लोटस' टैटू बनवाया था। यह उनकी जीवन यात्रा को प्रदर्शित करता है।

13.कोहली ने अपने बाएं हाथ पर एक नया टैटू बनवाया है। इसमें एक गोल डिजाइन है जो एक बीच के पॉइंट से निकलती हुई कई घुमावदार लाइनों से बना है। इसमें पानी में एक बूंद गिरने के बाद पानी की सतह पर लहर जैसा प्रभाव दिखता है।

फुटबॉल मैदान पर टक्कर के बाद जीसस डी मिगुएल की मौत, यूईएफए ने जताया शोक



न्योन (एजेंसी)

यूरोपीय फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था यूईएफए (यूईएफए) ने मंगलवार को सीडी टेनेरिफे के फॉरवर्ड जेसुस डी मिगुएल के निधन पर शोक व्यक्त किया। 30 वर्षीय खिलाड़ी का स्पेनिश सेकेंड डिवीजन के एक मैच के दौरान मैदान गंभीर टक्कर में चोटिल होने के बाद निधन हो गया।

यूईएफए के अध्यक्ष अलेक्जेंडर सेफेरिन ने कहा कि इस स्ट्राइकर के निधन से संगठन को गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने खिलाड़ी के परिवार, उनके साथियों और स्पेनिश क्लब से जुड़े सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, जीसस डी मिगुएल अलामेडा के निधन से हम बेहद दुखी हैं। हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं, बस सन्नाटा है। इस सन्नाटे के बीच, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, उनके साथियों, सीडी टेनेरिफे से जुड़े सभी लोगों और इस दुखद नुकसान पर शोक मनाने वाले हर व्यक्ति के साथ हैं।

सोमवार को 'एस्टाडियो हेलियोडोरो रोड्रिग्ज लोपेज' में एफसी अंडोरा के खिलाफ मुकाबले के दौरान, अंडोरा के गोलकीपर जीसस ओवोनों से टकराने के कारण डी मिगुएल के सिर और छाती में गंभीर चोटें आईं। यह हादसा मैच के आखिरी समय में हुआ। डी मिगुएल मिडफील्ड में गेंद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी गोलकीपर ओवोनों से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद मिगुएल मैदान पर बेहोश होकर गिर पड़े। घटना के तुरंत बाद मेडिकल टीम मैदान पर पहुंची और कई मिनट तक उनका इलाज किया। इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया।

'मैं अब युवा नहीं रही, बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल के लिया ब्रेक': पीवी सिंधु

नई दिल्ली (एजेंसी)



ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। सिंधु इस टूर्नामेंट के लिए ही ब्रेक लिया था। जापान ओपन सुपर 750 और जर्मनी में हाइलो ओपन में जीत हासिल करने के बाद पीवी सिंधु का आत्मविश्वास बढ़ा है। 2022 के बाद यह पहला सीजन है जिसमें सिंधु ने कई बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल जीते हैं।

पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने सारब्रुकेन में टूर्नामेंट से पहले फ्रेंच ओपन का फाइनल भी खेला था, लेकिन वह दुनिया की नंबर 1 और पेरिस 2024 चैंपियन कोरिया की एन से-यंग से हार गई थीं। हाइलो ओपन जीतने के कुछ दिनों बाद, सिंधु ने कोरिया ओपन और जापान मास्टर्स छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि उनका शुरुआती प्लान सभी टूर्नामेंट खेलने का था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने शरीर की सुनने और दिसंबर में होने वाले बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल के लिए आराम करने और फिट होने का फैसला किया। बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मीडिया बातचीत के दौरान एक सवाल पर सिंधु ने कहा, लंबा टूर खेलने के बाद, मैंने सोचा था कि मैं कोरिया ओपन और उसके बाद के टूर्नामेंट नहीं खेल पाऊंगी, लेकिन मेरे लिए वापस आकर आराम करना भी जरूरी था। मेरे लिए अपने शरीर का ध्यान रखना और अगले टूर्नामेंट के लिए फिट होना जरूरी था। यही प्लान था।

मुझे लगता है कि मेरे लिए यह फैसला लेना जरूरी था कि मैं नहीं खेलूंगी। मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है और कोर्ट पर फिर से मजबूती से वापस आना है। सिंधु ने कहा, मैं अब जवान नहीं रही, लेकिन मैंने यह भी कहा कि 31 अब नया 21 है, इसलिए मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है। नया 3म15 स्कोरिंग सिस्टम 4 जनवरी, 2027 से लागू होगा। सिंधु ने यह भी बताया कि क्या यह गेम को बदल देगा और क्या उनका गेम नए पॉइंट सिस्टम के हिसाब से सही होगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को शुरू से ही चौकन्ना रहने और आसान पॉइंट न गंवाने के लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। सिंधु ने कहा, 15 पॉइंट्स ऐसी चीज है जिस पर हर किसी को जरूर काम करना चाहिए, और हम इतने सालों से 21 पॉइंट्स पर खेल रहे हैं। इसलिए, हमने यह पक्का किया कि हम उस स्कोरिंग के लिए भी ट्रेनिंग और अभ्यास करें। हर किसी के लिए यह अलग होगा, इसलिए शुरू से ही अलर्ट रहना भी जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, यह जरूरी है कि आप शुरू से ही अलर्ट रहें। यह भी जरूरी है कि जब तक आपको पता चले कि आधा गेम खत्म हो गया है, तब तक आप कोई और आसान पॉइंट न दे सकें। इसलिए आपको हर बार चौकन्ना रहना होगा।

वर्ल्ड कप 2027 क्वालीफायर प्ले-ऑफ में जर्सी और कुवैत ने बनाई जगह

दुबई (एजेंसी)



जर्सी और कुवैत ने 'चैलेंज लीग ए' में शीर्ष दो स्थानों पर रहकर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदों को जिंदा रखते हुए आगामी क्वालीफायर प्ले-ऑफ में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। इस उपलब्धि के साथ जर्सी और कुवैत अब वर्ल्ड कप क्वालीफिकेशन की अगली अहम चुनौती में उतरेंगे, जहां उनके पास वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए आगे बढ़ने का मौका होगा।

चैलेंज लीग ए में लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत दोनों टीमों ने अपनी दावेदारी मजबूत की और शीर्ष दो में जगह बनाकर अगले चरण का टिकट हासिल किया। जर्सी ने 15 मुकाबलों के इस अभियान में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने केवल दो मैच हारे और दूसरे स्थान पर रहे कुवैत से 5 अंक आगे रहे। अब ये दोनों देश 8 टीमों वाले क्वालीफायर प्ले-ऑफ में हिस्सा लेंगे, जिससे यह तय होगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालीफायर में आखिरी 4 स्थान किन टीमों को मिलेंगे। वहीं, कुवैत ने अपने अभियान के अंत में शानदार प्रदर्शन किया और कुछ अहम नतीजों के उनके पक्ष में रहने से दूसरा स्थान हासिल कर लिया। वे डेनमार्क से 7 अंक आगे रहे। डेनमार्क को प्रतियोगिता के अंतिम चरण में केन्या और पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। क्वालीफायर प्ले-ऑफ में 'चैलेंज लीग ए' और 'चैलेंज लीग बी' की शीर्ष 2-2 टीमें, और 'क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2' की निचली 4 टीमें हिस्सा लेंगी। 50 ओवरों के क्वालीफिकेशन ढांचे में 'लीग 2', 'चैलेंज लीग' से ठीक ऊपर का स्तर है।

मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तोड़ा लगातार हार का सिलसिला, रोमा को 3-2 से हराया

मैनचेस्टर (एजेंसी)



मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दो गोल से पीछे रहने के बावजूद ओल्ड ट्रैफर्ड में शानदार वापसी करते हुए यूईएफए चैंपियंस लीग में रोमा को 3-2 से हराया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस जीत के साथ लगातार 9 मैचों में हार के सिलसिले को समाप्त किया। मटियास सोले ने मेहमान टीम के लिए पहला गोल किया, जिसके बाद डोनियल मालेन ने पेनल्टी को गोल में बदलकर शुरुआती 17 मिनट में स्कोर 2-0 कर दिया।

इन दो गोलों ने मैनचेस्टर यूनाइटेड पर दबाव बढ़ा दिया। यूनाइटेड के खिलाड़ियों को इसके बाद अपने समर्थकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पिच पर हरी टेनिस बॉल फेंकी गई और फुटबॉल डायरेक्टर जेसन विलकॉक्स के खिलाफ नारे लगाए गए। यूनाइटेड की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब मिडफील्डर कार्लोस बालेबा को हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई, जिससे कैरिक की पहले से ही मुश्किल शाम में एक और चिंता बढ़ गई। हालांकि, कप्तान ब्रूनो फर्नांडीस ने पेनल्टी को गोल में बदलकर यूनाइटेड की मैच में वापसी कराई। हालांकि, क्षेत्र के अंदर एक उल्लंघन के बाद उन्हें स्पॉट-किक दोबारा लेनी पड़ी क्योंकि उनकी पहली कोशिश बेकार हो गई थी। मोमेंटम धीरे-धीरे होम टीम की तरफ मुड़ गया, जब ब्रायन म्ब्यूमो ने दोनों पोस्ट पर शॉट मारकर यूनाइटेड को बराबरी पर लाने के बहुत करीब आ गए।

रोमा का विरोध आखिरकार तब टूट गया जब लियोनार्डो बालेरडी क्लीयरेंस से निपटने में नाकाम रहे, जिससे मैथ्यूस कुन्हा को फायदा उठाने और बराबरी करने का मौका मिल गया। मैच के आखिरी स्टेज पर, कुन्हा ने अहम झटका दिया, मुश्किल एंगल से एक जोरदार फिनिश के साथ गोल करके यूनाइटेड की जबरदस्त वापसी करवाई। कुन्हा के इस गोल ने ओल्ड ट्रैफर्ड में फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि, ब्राजील के इस खिलाड़ी को स्टॉपेज टाइम में बालेरडी पर फाउल करने के लिए दूसरा येलो कार्ड मिला। उन्हें पहले गोल सेलिब्रेशन के दौरान अपनी शर्ट उतारने के लिए बुक किया गया था, जिससे यूनाइटेड को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने पर मजबूर होना पड़ा।

मेजबान टीम ने 54 दिनों में अपनी पहली जीत हासिल की। इस जीत ने हेड कोच माइकल कैरिक पर दबाव हटाया। टीम की लगातार हार ने उन पर दबाव बढ़ा दिया था। यूनाइटेड को अपने अगले मैचों में एस्टन विला, लिवरपूल और स्पोर्टिंग सीपी जैसी टीमों का सामना करना है।

पहला वनडे : विराट कोहली का अर्धशतक, भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया

ऑकलैंड (एजेंसी)



ईडन पार्क में खेले गए पांच वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। भारत की जीत में अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी के बाद विराट कोहली की अर्धशतकीय पारी की अहम भूमिका रही। 186 का लक्ष्य हासिल करने उतरी भारतीय टीम को पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में 1 के स्कोर पर लगा। रोहित बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद गिल और विराट ने पारी को संभाला। बारिश की वजह से खेल दो बार बाधित हुआ।

दूसरी बार बारिश की बाधा के बाद जब खेल शुरू हुआ, तो डीएलएस नियम के मुताबिक भारत को जीत के लिए 32 ओवर में 143 का लक्ष्य मिला। शुभमन गिल और विराट ने दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी के दौरान लग रहा था कि भारत 9 विकेट से जीत हासिल करेगी, लेकिन ये साझेदारी टूटते ही लगातार विकेट गिरे। गिल दूसरे विकेट के रूप में 56 गेंदों पर 37 रन बनाकर 114 के स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद 124 के स्कोर पर विराट कोहली तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। विराट ने अर्धशतक लगाया। वे 51 गेंदों पर 1 छक्का और 13 चौकों की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए। 124 के स्कोर पर ही अक्षर पटेल बिना खाता खोले चौथे विकेट के रूप में आउट हुए।

श्रेयस अय्यर भी 13 गेंदों पर 15 रन बनाकर 136 के स्कोर पर पांचवें विकेट के रूप में आउट हुए। राहुल और नमन धीर ने भारतीय टीम को जीत दिलाई। भारत ने 5 विकेट पर 22.4 ओवर में 143 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता। राहुल 3 और धीर 5 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की तरफ से जैकब डफी ने 3, जबकि काइल जैमिसन और नाथन स्मिथ ने 1-1 विकेट लिए। इससे पहले, टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 40.2 ओवर में 185 रन पर सिमट गई थी। न्यूजीलैंड के लिए टिम सिफर्ट ने 38, डेरिल मिचेल ने 28 और ग्लेन फिलिप्स ने 30 रनों की पारी खेली। इसके अलावा, ब्लेयर टिकनर ने 34 और जैकब डफी ने नाबाद 15 रन बनाए थे। कीवी टीम ने एक समय 146 के स्कोर पर 9 विकेट गंवा दिए थे। ब्लेयर और डफी ने आखिरी विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 185 तक पहुंचाया। भारत की तरफ से अंशुल कंबोज ने बेहद किफायती गेंदबाजी की। कंबोज ने 10 ओवर में 2 मेडन फेंकते हुए मात्र 22 रन देकर 2 विकेट लिए।

केविन मीलामू ने विराट, रोहित और गिल को दी ऑल ब्लैक्स जर्सी

ऑकलैंड (एजेंसी)



न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे से पूर्व भारतीय खिलाड़ियों कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा को न्यूजीलैंड के पूर्व महान रग्बी खिलाड़ी केविन मीलामू से पर्सनलाइज्ड ऑल ब्लैक्स जर्सी दी। ऑकलैंड के ईडन पार्क में एक खास बातचीत के दौरान तीनों का ऑल ब्लैक्स परिवार में स्वागत किया गया, जहां मीलामू ने क्रिकेटरों को उनके क्रिकेट नंबर वाली एक काली जर्सी दी। गिल को 77, कोहली को 18 और रोहित को 45 नंबर की जर्सी दी गई। न्यूजीलैंड रग्बी के सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक, मीलामू ने 132 टेस्ट मैचों में ऑल ब्लैक्स का प्रतिनिधित्व किया। वह 2011 और 2015 में रग्बी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 4 नवंबर को मशहूर ऑकलैंड वेन्यू पर शुरू हुई पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय स्टार्स के साथ उनकी मीटिंग ने एक स्पोर्टिंग क्रॉसओवर का मौका दिया। ईडन पार्क न्यूजीलैंड के स्पोर्टिंग इतिहास में एक खास जगह रखता है, जो देश के सबसे मशहूर रग्बी वेन्यू में से एक है। यह स्टेडियम ऑल ब्लैक्स के शानदार 54 मैचों के बिना हारे होम रन से भी जुड़ा है, जो 1994 में शुरू हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम ने सोशल मीडिया पर इस बातचीत की साझा की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इसे तीन भारतीय स्टार्स और न्यूजीलैंड रग्बी के एक महान खिलाड़ी से जुड़ा एक खास पल बताया। यह मीटिंग दो खेलों से आगे बढ़कर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच स्पोर्टिंग रिश्तों के सौ साल पूरे होने के जश्न के दौरान हुई। इस रिश्ते की शुरुआत 1926 में हुई थी, जब महान खिलाड़ी ध्यानचंद की मौजूदगी में इंडियन आर्मी की हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड का ऐतिहासिक दौरा किया था। अभी चल रहा सभी फॉर्मेट का क्रिकेट दौरा दोनों देशों के बीच खेलों के 100 साल पूरे होने के जश्न का हिस्सा है। भारत पहले ही पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से जीत चुका है। मेजबान टीम साझा खेल और सांस्कृतिक विरासत को याद करने के लिए एक खास लिमिटेड-एडिशन कोटाहितंगा वनडे जर्सी भी पहन रही है। वनडे सीरीज के बाद दो टेस्ट मैचों की सीरीज वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में खेली जाएगी।

डब्ल्यूटीए फाइनल्स ड्रॉः पहले मैच में रायबाकिना का मुकाबला नोस्कोवा से और सबालेंका का मुचोवा से

नई दिल्ली (एजेंसी)



दुनिया की नंबर 1 और डिफेंडिंग चैंपियन एलेना रायबाकिना को डब्ल्यूटीए फाइनल्स के नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्ता दिया गया है। 27 साल की इस खिलाड़ी को ग्रुप 1 में कोको गॉफ और जेसिका पेगुला की अमेरिकी जोड़ी और विंबलडन चैंपियन लिंडा नोस्कोवा के साथ रखा गया है। इस इवेंट में दुनिया की टॉप आठ महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें दो चार-खिलाड़ियों के ग्रुप में बांटा गया है, जो 8 नवंबर से शुरू होने वाले राउंड-रॉबिन इवेंट में आमने-सामने होंगी, जिससे चार सेमीफाइनलिस्ट तय होंगे। सेमीफाइनल 14 नवंबर को खेले जाएंगे, और जीतने वाली टीमें 15 नवंबर को टाइटल के लिए आमने-सामने होंगी। पिछले दो मेजर चैंपियन, रायबाकिना और नोस्कोवा के बीच 2026 की पहली मुलाकात, डब्ल्यूटीए फाइनल्स की शुरुआत होगी। मार्च में इंडियन वेल्स चैंपियनशिप मैच में आर्यना सबालेंका से हारने वाली रायबाकिना 2013-14 में सेरेना विलियम्स के बाद पहली बार डब्ल्यूटीए फाइनल्स टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड करना चाहती हैं। इस साल की शुरुआत में विंबलडन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के बाद, युवा चेक खिलाड़ी साल के आखिर में होने वाली चैंपियनशिप में अपने डेब्यू में कुछ खास करने के लिए बेताब होंगी। दोनों की आखिरी मुलाकात 2025 में वुहान में हुई थी, जहां रायबाकिना ने हेड-टू-हेड में लगातार तीसरी जीत हासिल की थी।

एक्स ने हाथ काटकर मांग भरने की कोशिश की थी, कनिका मान के रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे



'बिग बॉस 20' के घर में टीवी अभिनेत्री कनिका मान ने अपने अतीत का एक ऐसा खौफनाक पन्ना खोला है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। कनिका ने खुलासा किया कि कॉलेज के दिनों में वह एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गई थीं, जहां उन्हें शारीरिक हिंसा और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। अभिनेत्री ने बताया कि उनके एक्स-बॉयफ्रेंड ने न सिर्फ कॉलेज में सबके सामने उन पर हाथ उठाया, बल्कि खुद को चाकू मारकर खून से उनकी मांग भरने की कोशिश भी की थी। कनिका मान ने बताया कि कॉलेज के शुरुआती दिनों में सोशल मीडिया के जरिए वह उस लड़के के संपर्क में आई थीं, लेकिन बाद में समझ आया कि वह दिमागी रूप से ठीक नहीं था। अपने साथ हुई हिंसा को याद करते हुए कनिका ने कहा, 'वह मारपीट करने वाला इंसान था। बिना बताए मेरी क्लास में आ धमकता था। एक बार मैंने स्ट्राइप्स वाला सूट पहना था, जिस पर उसने सबके सामने कॉरिडोर में मुझे थप्पड़ जड़ दिया।' कनिका ने बताया कि उस समय उन्होंने कान में नई पियर्सिंग कराई थी और जोरदार थप्पड़ की वजह से कान से खून बहने लगा था। अभिनेत्री ने आगे बताया कि वह शख्स उन्हें लगातार डराता-धमकाता था और उनका फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया करता था। कनिका ने कहा, उसने मुझे हर तरह से लाचार कर दिया था। वह कहता था कि मेरे साथ चल, वरना तेरे पापा को फोन करके बोल दूंगा कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूं। उसने मेरे पापा को फोन भी किया था, लेकिन गनीमत रही कि उन्होंने उठाया नहीं। वह मुझे ब्लैकमेल करता था, लेकिन चूंकि मैं लॉ की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मुझे धीरे-धीरे चीजें समझ आने लगी थीं। उस रिश्ते की सबसे डरावनी घटना का जिक्र करते हुए कनिका ने बताया, 'एक दिन उसने हॉस्टल से डिपार्टमेंट तक मेरा पीछा किया। उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। उसके हाथ में चाकू था, जिससे उसने खुद पर ही 3-4 बार वार किए। फिर मेरे बाल खींचकर बोला कि इस खून से तेरी मांग में सिंदूर लगाऊंगा। कनिका ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और वहां से गुजर रहे एक लड़के से पुलिस बुलाने की गुहार लगाई। **(एजेंसी)**

कपूर परिवार में क्यों नहीं होती बेटों के काम की तारीफ? रणबीर ने बताई पीढ़ियों पुरानी परंपरा

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने कपूर परिवार की एक ऐसी परंपरा के बारे में बात की, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। उन्होंने बताया कि इस परिवार में पिता अपने बेटों के काम की खुलकर तारीफ करने से बचते रहे हैं। इसके पीछे वजह बेटों को लगातार बेहतर करने और अपने काम के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करना रही है।
रणबीर ने अपने दादा राज कपूर और परदादा पृथ्वीराज कपूर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। रणबीर ने यह किस्सा मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में बातचीत के दौरान साझा किया। रणबीर के कहा, 'मैंने यह कहानी राज कपूर की किताब में पढ़ी थी। एक बार राज कपूर ने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से पूछा था कि जब उनका बेटा आज इतना बड़ा स्टार बन चुका है और फिल्मों में इतना अच्छा काम कर रहा है, तो वे कभी उनकी तारीफ क्यों नहीं करते? यहां तक कि कभी पीठ थपथपाकर शाबाशी भी नहीं देते।' रणबीर ने आगे बताया, ''इस सवाल के जवाब में पृथ्वीराज कपूर ने राज कपूर को एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि एक छोटा लड़का सड़क किनारे रस्सी पर संतुलन बनाकर करतब दिखाता था। उसका प्रदर्शन देखने के लिए रोज बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे।



लोग तालियां बजाते, उसे पैसे देते और उसकी जमकर तारीफ करते थे। हर बार करतब खत्म होने के बाद वह बच्चा अपने पिता के पास जाता और उनसे पूछता कि उसका प्रदर्शन कैसा रहा। लेकिन पिता हर बार उसे एक ही जवाब देते थे- 'कसर रह गई।' लोगों से इतनी तारीफ मिलने के बावजूद पिता उसे यही समझाते कि उसके प्रदर्शन में अभी सुधार की गुंजाइश बाकी है।' अभिनेता ने बताया, 'कई सालों तक ऐसा होने के बाद एक दिन उस बच्चे ने अपने पिता से पूछ ही लिया कि जब लोग उसके करतब की इतनी तारीफ करते हैं और उसे इतना अच्छा बताते हैं, तो उसके पिता हमेशा कमी ही क्यों निकालते हैं? इस पर पिता ने जो जवाब दिया, वह काफी गहरी सीख देने वाला था।' रणबीर के बताया कि बच्चे के पिता ने उससे कहा था, 'बेटा, जिस दिन मैं तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर दूंगा, उस दिन तुम्हारा लक्ष्य और ध्यान अपने काम से हट जाएगा। तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने के बजाय तारीफ में ही खो जाओगे।' रणबीर की कहा, कपूर परिवार में बच्चों को कामयाबी मिलने के बाद भी लगातार मेहनत करते रहने की सीख दी जाती रही है। परिवार के बड़े तारीफ और वाहवाही के बजाय अपने काम को बेहतर बनाने पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। **(एजेंसी)**



रश्मिका के लहजे पर ट्रोलिंग के बीच कशिका कपूर का समर्थन, बोलीं- भाषा रुकावट नहीं होनी चाहिए

अभिनेत्री कशिका कपूर ने दक्षिण भारतीय अभिनेताओं के बॉलीवुड में काम करने के दौरान उनके हिंदी लहजे को लेकर ट्रोल किए जाने पर अपनी राय साझा की। कशिका ने कहा कि एक एक्टर को एक कलाकार के रूप में देखा जाना चाहिए और भाषा उनके लिए कोई रुकावट नहीं बननी चाहिए। उनसे पूछा गया, कभी-कभी हिंदी फिल्मों में काम करने वाले दक्षिण भारतीय एक्टर्स को उनके बोलने के लहजे की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ता है। किसी एक्टर को उसकी भाषा या एक्सेंट के आधार पर जज करने के बारे में आपकी क्या राय है? इस पर कशिका ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसा अक्सर होता है, लेकिन एक एक्टर की पहचान हमेशा एक परफॉर्मर के तौर पर होनी चाहिए। भाषा कभी कोई रुकावट नहीं बननी चाहिए। हमें इंडस्ट्री को यह कहकर नहीं बांटना चाहिए कि यह तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है या यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। 'कॉफी विद करण' में शामिल होने के दौरान रश्मिका मंदाना ने बताया था कि उन्हें अपने पूरे करियर में अपने एक्सेंट को लेकर आलोचना झेलनी पड़ी है। हालांकि, उन्होंने कभी इस आलोचना की वजह से खुद को अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री और भाषाओं में काम करने से रोकने नहीं दिया। शो के दौरान रश्मिका ने बताया कि वह दक्षिण भारत से हैं, इसलिए उनका एक्सेंट स्वाभाविक है। 'पुष्पा' एक्ट्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि वह खुद को सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित रखने के बजाय कई भाषाओं में काम करना चाहती हैं। रश्मिका का उदाहरण देते हुए कशिका ने कहा कि 'द गर्लफ्रेंड' फिल्म की इस एक्ट्रेस को जिस तरह की आलोचना या जजमेंट का सामना करना पड़ रहा है, वह उसकी हकदार नहीं हैं। कशिका ने कहा, हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। उदाहरण के लिए रश्मिका मंदाना को ही ले लीजिए। वह एक शानदार एक्टर और परफॉर्मर हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उन्हें उनकी भाषा या एक्सेंट के आधार पर जज करना चाहिए। यह उनकी पहचान का ही एक हिस्सा है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। उनकी जड़ें वहां से जुड़ी हैं, लेकिन अंत में उनकी परफॉर्मेंस ही मायने रखती है। वह 'एनिमल' जैसी कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक्टर्स को उनके एक्सेंट के लिए जज करने के बजाय, उनके टैलेंट के लिए सराहा जाना चाहिए। **(एजेंसी)**



पचास करोड़ डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाले भारतीय स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 51 पर : रिपोर्ट

मुंबई (एजेंसी)



भारतीय स्टार्टअप में 50 करोड़ डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली कंपनियों की संख्या 2026 में बढ़कर 51 हो गई है। यह एक साल पहले 47 थी। कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र की कंपनियों की संख्या कम होने के बावजूद यह वृद्धि हुई है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। एएसके प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया गजेल इंडेक्स, 2026' की रिपोर्ट के अनुसार, इन 51 कंपनियों का कुल मूल्यांकन करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये (34.1 अरब डॉलर) है।

इनका औसत मूल्यांकन करीब 6,400 करोड़ रुपये है और ये 60,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इन कंपनियों का कुल राजस्व 33,233 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 50 प्रतिशत बढ़ा है। हुरुन इंडिया के संस्थापक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा कि इस सूची में एआई क्षेत्र की केवल तीन कंपनियां- एमा एआई, ऑब्जर्व एआई और यूनिफाईएप्स शामिल हैं। यह संख्या अमेरिका की 54 और चीन की 23 ऐसी कंपनियों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद 50 करोड़ डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली भारतीय कंपनियों की संख्या इस साल बढ़कर 51 हो गई है। एआई क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की कमी को अक्सर भारतीय शेयर बाजारों से विदेशी निवेशकों की निकासी का एक प्रमुख कारण बताया जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में सात स्टार्टअप कंपनियों का मूल्यांकन एक अरब डॉलर के पार पहुंच गया और वे यूनिकॉर्न बन गईं। इनमें ट्विन हेल्थ का मूल्यांकन 70 करोड़ डॉलर से बढ़कर दो अरब डॉलर हो गया। इन सात में से छह कंपनियां वित्तीय सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ी हैं। एएसके प्राइवेट वेल्थ के सह-संस्थापक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक राजेश सलूजा ने कहा, 'यह उद्यमिता के ऐसे आधार को दर्शाता है जो विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता वाले कारोबार खड़े कर रहा है।' रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते क्षेत्रों में एआई और स्वच्छ प्रौद्योगिकी सबसे बड़े क्षेत्र हैं। इन दोनों क्षेत्रों में तीन-तीन स्टार्टअप कंपनियां हैं। एआई समूह में एमा एआई, ऑब्जर्व एआई और यूनिफाईएप्स शामिल हैं, जबकि स्वच्छ प्रौद्योगिकी समूह में कार्बन क्लीन सॉल्यूशंस, लोहुम और रेजॉन सोलर हैं।

न्यायालय ने राज्यों के अतिरिक्त बिक्री कर लगाने के अधिकार को बरकरार रखा, 1974 का फैसला अब भी प्रभावी

नई दिल्ली (एजेंसी)

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि 1974 में संविधान पीठ का वह फैसला अब भी प्रभावी है, जिसमें राज्यों के मौजूदा बिक्री कर के प्रतिशत के आधार पर अतिरिक्त बिक्री कर या अधिभार लगाने के अधिकार को बरकरार रखा गया था।

न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार के लिए भेजे गए संदर्भ पर अब फैसला देने की जरूरत नहीं रह गई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि करीब 27 साल पहले उसके पास भेजे गए कानूनी सवाल पर अब निर्णय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनौती दिए गए वैधानिक प्रावधानों को तब से बदला जा चुका है या उनमें संशोधन किया जा चुका है और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू हो चुका है। प्रधान न्यायाधीश ने अपने और पांच अन्य न्यायाधीशों की ओर से फैसला लिखते हुए कहा, 'संदर्भित सवाल का अब कोई व्यावहारिक महत्व नहीं रह गया है और यह अकादमिक हो चुका है। इसलिए, सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस सवाल पर निर्णय किए जाने की जरूरत नहीं रह गई है और संदर्भ का जवाब इसी के अनुरूप दिया जाना चाहिए।' पीठ में न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन, न्यायमूर्ति एस. वी. भट्टी, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने अलग से सहमति वाला फैसला लिखा।

'पता नहीं कहां लैंड करूंगा...' सलमान खान ने अपनी आवाज में रिलीज किया नया गाना

अभिनेता सलमान खान ने बुधवार को अपने फैंस के लिए अपनी आगामी वॉर-ड्रामा फिल्म 'मातृभूमिः मे वॉर रेस्ट इन पीस' का नया गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' रिलीज कर दिया है, जिसके रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अभिनेता सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अभिनेता सलमान रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हुए और अपने खास अंदाज में गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। गाने के प्रमोशनल पोस्टर में सलमान खान नजर आ रहे हैं। पोस्टर में वह हेडफोन पहने हुए मुस्कुरा रहे हैं और गाना सुन रहे हैं। पोस्टर पर दिए गए क्रेडिट के मुताबिक, 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' हिमेश रेशमिया का म्यूजिकल है, जिसे सलमान खान और गायिका मुस्कान ने मिलकर गाया है, जबकि संगीत साजिद खान ने तैयार किया है और इसके बोल भी उन्होंने ही लिखे हैं। उन्होंने लिखा, डिपार्चर टाइम सुबह 5:12 बजे, फ्लाइट टाइम पर है, 2 पैग हो चुके हैं, अपनी सेक्सी ब्यूटी के साथ उड़ान भर रहा हूं, पता नहीं कहां लैंड करूंगा। गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' रिलीज हो गया है। ऐसा पहली बार नहीं है, जब सलमान ने किसी गाने को अपनी आवाज दी हो। पिछले कई सालों में सलमान ने अपनी फिल्मों के लिए कई गाने गाए हैं, जिनमें 'हैलो ब्रदर' का 'चांदी की डाल पर' भी शामिल है, जो उनके शुरुआती गानों में से एक था। इसके बाद उन्होंने 'वांटेड' के 'मोस्ट वांटेड ट्रैक', 'किक' के 'हैंगओवर', 'तू ही तू' और 'है यही जिंदगी' में अपनी आवाज दी। उनके दूसरे पॉपुलर गानों में 2015 की फिल्म 'हीरो' का 'मैं हूं हीरो तेरा', 'सुल्तान' का 'बेबी को बास पसंद है' और 'जग घूमेया' शामिल हैं। उन्होंने 2020 में कोरोना महामारी के दौरान 'प्यार करोना', 'तेरे बिना' और 'भाई भाई' जैसे कई इंडिपेंडेंट गाने भी रिलीज किए थे।

केकेआर को जेंटारी रिन्यूएबल्स में हिस्सेदारी खरीदने के लिए सीसीआई की मंजूरी मिली

नई दिल्ली (एजेंसी)



वैश्विक निवेश कंपनी केकेआर को प्रतिस्पर्धा नियामक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से मलेशिया की ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी पेट्रोनास के स्वच्छ ऊर्जा मंच जेंटारी रिन्यूएबल्स इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मंगलवार को कहा कि केकेआर अपनी सहयोगी कंपनी सैफायर यूएस होल्डको (यूएसए) एलएलसी के जरिये यह निवेश कर रही है। यह कंपनी जेंटारी रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कुछ प्रतिभूतियों की सदस्यता लेगी। जेंटारी रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों एवं बैटरी ऊर्जा भंडारण समाधानों के जरिये बिजली उत्पादन के कारोबार में लगी है।

यह पेट्रोलियम नैशनल बरहाद (पेट्रोनास) की अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है और मलेशिया की बहुराष्ट्रीय तेल एवं गैस कंपनी पेट्रोनास समूह का हिस्सा है। यह मंजूरी अक्टूबर में घोषित प्रस्तावित निवेश के बाद मिली है। इसके तहत केकेआर मलेशिया की सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी पेट्रोनास के समर्थन वाले भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार में करीब 6,000 करोड़ रुपये में हिस्सेदारी खरीदेगी। हीरो फ्यूचर एनर्जीज, सेंरेंटिका रिन्यूएबल्स और इंडिग्रिड सहित केकेआर पहले भी भारत के स्वच्छ ऊर्जा और बिजली बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश कर चुकी है।

देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियां अक्टूबर में 4 महीने के उच्चतम स्तर पर

नई दिल्ली (एजेंसी)



देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में अक्टूबर में चार महीने की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई। मांग में मजबूती से कारोबारी गतिविधियों और नए ऑर्डर में बढ़ोतरी हुई, जबकि लागत का दबाव कम हुआ। बुधवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई। कंपनियां भविष्य की संभावनाओं को लेकर सतर्कता के साथ आशावादी रहीं और उन्होंने चार महीने में सबसे कम संख्या में कर्मचारियों की भर्ती की।

अंतरराष्ट्रीय बिक्री में ताजा विस्तार लगभग चार साल में सबसे कमजोर रहा। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक सितंबर के 55.2 से बढ़कर अक्टूबर में 55.8 हो गया। यह चार महीने में वृद्धि की सबसे तेज रफ्तार को दर्शाता है। क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की भाषा में 50 से ऊपर का अंक विस्तार, जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन दर्शाता है। एचएसबीसी की मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) प्रांजुल भंडारी ने कहा, 'भारत का सेवा पीएमआई अक्टूबर में बढ़कर 55.8 हो गया, जो चार महीने का उच्चतम स्तर है। इस दौरान कारोबारी स्थितियों में सतर्कता के साथ सुधार हुआ। हालांकि, कुल मांग काफी मजबूत बनी रही लेकिन नए निर्यात ऑर्डर में वृद्धि की रफ्तार फरवरी 2023 के बाद सबसे धीमी रही।' सर्वेक्षण में शामिल कंपनियों ने उत्पादन में वृद्धि की मुख्य वजह नए कारोबार में बढ़ोतरी को बताया।

सर्वेक्षण के अनुसार, मांग की अनुकूल परिस्थितियों, नए ग्राहक मिलने और सफल विज्ञापन अभियानों से नए ऑर्डर बढ़े। कीमतों के मोर्चे पर लागत का दबाव काफी कम हुआ। भंडारी ने कहा, 'कच्चे माल और तैयार उत्पादों की कीमतों में वृद्धि जारी रही लेकिन इसकी रफ्तार पिछले महीने के मुकाबले धीमी रही। इससे महंगाई के दबाव में कुछ राहत मिलने के संकेत मिलते हैं।' उन्होंने कहा कि रोजगार में वृद्धि की रफ्तार भी जून के बाद सबसे कमजोर रही। इससे संकेत मिलता है कि सेवा क्षेत्र की कुछ कंपनियों के पास मौजूदा कर्मचारियों की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। कंपनियां भविष्य की संभावनाओं को लेकर हालांकि सतर्कता के साथ आशावादी रहीं और उन्होंने चार महीने में सबसे कम संख्या में कर्मचारियों की भर्ती की।

इस बीच, भारत का समग्र पीएमआई उत्पादन सूचकांक सितंबर के 55.9 से बढ़कर अक्टूबर में 56.2 हो गया। यह चार महीने में कुल उत्पादन में सबसे तेज वृद्धि को दर्शाता है और कारोबारी गतिविधियों की मजबूत स्थिति का संकेत देता है।